अप्रैल–2026

मूल्य ₹ 30/-

UPHIN/25/A4962

न्यूज ड्रिफ्ट

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

यूपी के 9 साल बेमिसाल

स्वप्न से यथार्थ तक

इंफ्रास्ट्रक्चर

निवेश और रोजगार

कृषि विकास

NEWS DRIFT

की विशेष पहल

CLIMATE WARRIOR

(जलवायु योद्धा)

बच्चों की आवाज़ – धरती की सुरक्षा

हर बच्चा बनेगा
जलवायु योद्धा
हर घर बनेगा
पर्यावरण प्रहरी

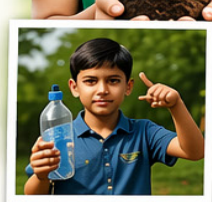

सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें

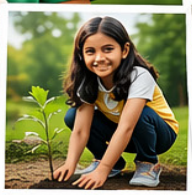

पेड़ लगाएं, धरती बचाएं

चीजों को री-यूज करें, पर्यावरण को सुरक्षित करें

News Drift बच्चों को जोड़ रहा है जलवायु संरक्षण के मिशन से। अपना छोटा सा वीडियो संदेश या निबंध भेजें और बनें सच्चे पर्यावरण प्रहरी।

भाग लेने के तरीके

1. वीडियो संदेश

- ✓ 30–60 सेकंड का छोटा वीडियो
- ✓ जलवायु संरक्षण पर अपना संदेश दें
- ✓ उदाहरण:
  - सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की अपील
  - पेड़ लगाते हुए वीडियो
  - चीजों को री-यूज / रिसायकल करते हुए
- ✓ भाषा: हिंदी / अंग्रेजी / स्थानीय भाषा

2. निबंध प्रतियोगिता

- ✓ 100–300 शब्द
- ✓ विषय: मेरा योगदान पृथ्वी को बचाने में

हर बच्चे की आवाज़, लाखों तक!

आपका वीडियो
NEWS DRIFT के
YOUTUBE CHANNEL
पर प्रकाशित होगा

और NEWS DRIFT के
INSTAGRAM CHANNEL
पर भी साझा किया जाएगा

बच्चों को क्या मिलेगा?

- Climate Warrior Certificate (सभी प्रतिभागियों के लिए)
- हर प्रतिभागी को एक पौधा (Sapling)
- आपका वीडियो YouTube और Instagram पर प्रकाशित होगा
- पहचान, सराहना और पर्यावरण के लिए सकारात्मक योगदान

श्रेष्ठ निबंध लेखक पुरस्कार

1st PRIZE	2nd PRIZE	3rd PRIZE
₹5000 + MOMENTO + MEDAL	₹2000 + MEDAL	₹1000 + MEDAL

स्कूलों के लिए विशेष

- ✓ बड़े स्तर पर सहभागिता के लिए विशेष सहयोग
- ✓ सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाणपत्र
- ✓ आपके स्कूल का नाम और वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होगा
- ✓ पर्यावरण शिक्षा और गतिविधि में स्कूल की सकारात्मक पहचान

सहभागिता शुल्क

₹80
प्रति प्रतिभागी

अपनी प्रविष्टि भेजें

WhatsApp: 9451760655
Email: newsdrift19@gmail.com
Website: www.newsdrift.in

वीडियो या निबंध के साथ छात्र का नाम, कक्षा, स्कूल का नाम और संपर्क नंबर अवश्य भेजें।

अंतिम तिथि

30 जून 2025

आज ही भाग लें और बनें
CLIMATE WARRIOR!

NEWS DRIFT | आइए, मिलकर धरती को बेहतर और सुरक्षित बनाएं!

न्यूज ड्रिफ्ट

वर्ष–1 अंक–04 अप्रैल–2026

संरक्षक
पं० आदित्य द्विवदी

संपादक
रवि कान्त

सह संपादक
श्वेता शुक्ला

ब्यूरो चीफ लखनऊ
पंकज द्विवेदी

ग्राफिक्स डिजाइनर
अरूण मिश्र

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक

''यह मासिक पत्रिका रवि कान्त द्वारा 537भ /236 भरत नगर, मोहिबुल्लापुर लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226021 से रवि कान्त के स्वामित्व में प्रकाशित की जाती है, जिसके संपादक रवि कान्त हैं और यह नीलम प्रिंटिंग प्रेस, 41/381, नरही लखनऊ उत्तर प्रदेश–226001 पर नीलम श्रीवास्तव द्वारा मुद्रित की जाती है।''

Mob. 9451760655
Email :-
newsdrift19@gmail.com
Website :-
WWW.NEWSDRIFT.IN
RNI-UPHIN/25/A4962

पत्रिका में प्रकाशित लेख व समाचारों में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। उसका लेखक ही उत्तरदायी होगा।

समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र माननीय न्यायालय लखनऊ होगा।

कीर्तिमानों का प्रदेशः जहाँ यूपी ने गाड़े सफलता के झंडे – 05

जन-जन की ढालः उत्तर प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा –10

उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांतिः रिकॉर्ड उत्पादन से लेकर चुनौतियों के समाधान तक –12

थल, जल, नभः उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व कनेक्टिविटी क्रांति–31

सम्पादक की कलम से ....

न्यूज ड्रिफ्ट: शोर से अलग एक शुरुआत

आज का समय सूचनाओं की बाढ़ का है। हर पल, हर स्क्रीन पर खबरें हैं–तेज, चटख और अक्सर अधूरी। इस शोर में सच कई बार दब जाता है, संदर्भ खो जाता है और समझ पीछे छूट जाती है। ऐसे दौर में न्यूज ड्रिफ्ट की यह शुरुआत उसी खामोशी से जन्म लेती है, जो शोर से अलग होकर सोचने का अवसर देती है।

न्यूज ड्रिफ्ट का उद्देश्य केवल खबर देना नहीं, बल्कि खबर के अर्थ को सामने रखना है। हम मानते हैं कि पत्रकारिता का काम सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि समय रहते चेतावनी देना, सवाल उठाना और नागरिकों को समझ से लैस करना है।

यह पत्रिका राजनीति, समाज, पर्यावरण और नागरिक जीवन से जुड़े मुद्दों को तथ्यों, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करने का संकल्प लेती है। हम पक्षधरता से अधिक पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं; शोर से अधिक संदर्भ में; और तात्कालिक प्रतिक्रियाओं से अधिक दीर्घकालिक सोच में। न्यूज ड्रिफ्ट उस पत्रकारिता का पक्षधर है, जो डर नहीं फैलाती–समझ पैदा करती है।

पत्रिका के रूप में यह शुरुआत हमारे लिए एक वादा है– पाठकों से भी और स्वयं से भी। यह वादा कि हम आसान रास्ता नहीं चुनेंगे, जटिल सवालों से नहीं बचेंगे और जनहित को प्राथमिकता देंगे। हमें भरोसा है कि पाठक भी ऐसी पत्रकारिता के सहभागी बनेंगे, जो खबर को उपभोग नहीं, संवाद बनाती है।

यह पहला कदम है। आगे की राह लंबी है और चुनौतियाँ भी होंगी। लेकिन यदि पत्रकारिता को फिर से भरोसे, विवेक और संवेदना से जोड़ना है, तो शुरुआत शोर से अलग होकर ही करनी होगी। न्यूज ड्रिफ्ट उसी अलग शुरुआत का नाम है, जहाँ खबरें सिर्फ पढ़ी नहीं जातीं, समझी जाती हैं।

संपादक

रवि कान्त

कीर्तिमानों का प्रदेश: जहाँ यूपी ने गाड़े सफलता के झंडे

- आज का उत्तर प्रदेश विकास के उस पायदान पर खड़ा है जहाँ 'नंबर 1' होना अब इसकी आदत बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल क्रियान्वयन ने प्रदेश को उन ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया है, जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक कठिन थी।
- प्रदेश कुल खाद्यान्न उत्पादन के साथ, गेंहू, धान, केला, आलू, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, मेथा, चीनी और शहद उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है।
- हालिया आंकड़ों के अनुसार, दुग्ध उत्पादन में प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। देश के कुल दूध उत्पादन में लगभग 16% की हिस्सेदारी के साथ यूपी अब पहले स्थान पर है।
- गन्ने से एथेनॉल उत्पादन और इसकी आपूर्ति में भी यूपी देश का 'पावरहाउस' बनकर उभरा है। 2025–26 में 187.80 करोड़ लीटर का एथेनॉल उत्पादन।
- (Government e-Marketplace) पोर्टल के माध्यम से खरीदारी करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रदेश ने रु.22,337 करोड़ से अधिक की खरीद कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और MSMEs को सशक्त बनाया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के तहत 56 लाख से अधिक घरों का निर्माण कर यूपी नंबर 1 बना हुआ है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना (रु.9.57 करोड़ खाते), स्वच्छ भारत मिशन (2.68 करोड़ शौचालय) और उज्ज्वला योजना (1.85 करोड़ गैस कनेक्शन) के क्रियान्वयन में भी प्रदेश का रिकॉर्ड सबसे शानदार है।
- महाकुंभ 2025 के ऐतिहासिक आयोजन ने जहाँ 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को आकर्षित किया, वहीं अयोध्या, काशी और मथुरा–वृंदावन जैसे केंद्रों ने यूपी को घरेलू पर्यटन में देश का नंबर 1 राज्य बना दिया है।
- अयोध्या में दीपोत्सव 2024 में 25 लाख से अधिक दीप जलाकर बना 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' यूपी की सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रमाण है।
- अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री

सुरक्षा बीमा योजना के तहत सर्वाधिक नामांकन सुनिश्चित कर प्रदेश ने एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया है।

- पीएम स्वनिधि योजना के तहत 20 लाख से अधिाक रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण देकर उनके जीवन को सुगम बनाया गया है।
- प्रदेश में वर्तमान में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं जो देश में किसी भी राज्य में सर्वाधिक हैं।
- कौशल विकास नीति को लागू करने वाला यूपी पहला राज्य है और एनपीएस और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण में अग्रणी राज्य है।
- उत्तरप्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है।
- भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इकाइयाँ प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।
- एक्सप्रेसवे के मामले में उत्तरप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में 22 एक्सप्रेसवे (7 संचालित, 5 निर्माणाधीन और 10 प्रस्तावित) का प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हैं।
- प्रदेश में देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क (16000 किलोमीटर) है।
- देश के 111 जलमार्गों में से 11 उत्तरप्रदेश में है।
- लैंडलॉकेड राज्यों में उत्तरप्रदेश एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर है।
- जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रारंभ होते ही उत्तरप्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहाँ 5 अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे।
- सौभाग्य योजना के अंतर्गत पूरे देश में निर्गत विद्युत संयोजन के सापेक्ष उत्तरप्रदेश द्वारा देश में सर्वाधिक संयोजन निर्गत किये गए। जिसके लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा उत्तरप्रदेश को पुरस्कृत किया गया।
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कार्यों में उत्तरप्रदेश राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
- नवीनतम वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अनुसार GVA में 25% की वृद्धि। देश के सभी प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान।
- प्रति वर्ष 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन करते हुए देश में प्रथम स्थान पर।
- उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत रिकॉर्ड 62 लाख से अधिक पक्के घर बनाकर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य में 2.58 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 37,998 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देशभर में प्रथम (अग्रणी) स्थान पर है। राज्य में 1.86 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए हैं।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण वितरण में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।
- उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) स्थापित करने में देश में अग्रणी राज्यों में से एक है, जहाँ 90 लाख से अधिक (कुछ आंकड़ों के अनुसार 96 लाख से ज्यादा) इकाइयों के साथ सबसे बड़ा MSME आधार मौजूद है।

अंधेरे से आत्मनिर्भरता तक: सरप्लस बिजली की तरफ अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश ने बीते वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव दर्ज किया है। 2017 तक जहां केवल लगभग 1.28 लाख मजरों तक ही बिजली पहुंची थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर करीब 2.94 लाख मजरों तक पहुंचाया गया है। इससे प्रदेश में लगभग शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल हुआ है और गांव-गांव तक रोशनी पहुंची है।

बिजली आपूर्ति के घंटों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आज जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 22 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे और कृषि फीडरों पर लगभग 10 घंटे तक बिजली दी जा रही है। यह बदलाव सीधे तौर पर आम जनता और किसानों के जीवन को आसान बना रहा है।

ऊर्जा ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। वर्ष 2017 से नवंबर 2025 तक 15.87 लाख से अधिक नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए गए हैं, जिससे कुल संख्या बढ़कर 27.91 लाख से ज्यादा हो गई है। साथ ही 765 नए 33/11 केवी सब-स्टेशन बनाए गए हैं, जिससे कुल संख्या 4,582 तक पहुंच गई है।

प्रसारण क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाकर 31,500 मेगावाट किया गया है, जो 2016-17 में 17,890 मेगावाट थी। वहीं विद्युत आयात क्षमता भी 7,800 मेगावाट से बढ़ाकर 16,700 मेगावाट कर दी गई है। हजारों किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं, जिससे आपूर्ति और अधिक भरोसेमंद बनी है।

उत्पादन क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हुई है। प्रदेश की कुल स्थापित क्षमता 29,750 मेगावाट से बढ़कर 32,259 मेगावाट हो गई है, जबकि कुल अनुबंधित क्षमता 55,860 मेगावाट तक पहुंच चुकी है।

खुरजा, घाटमपुर और जवाहरपुर जैसी तापीय परियोजनाओं से उत्पादन शुरू होने से राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट मीटरिंग और लाइन लॉस कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 59 लाख से अधिक उपभोक्ताओं

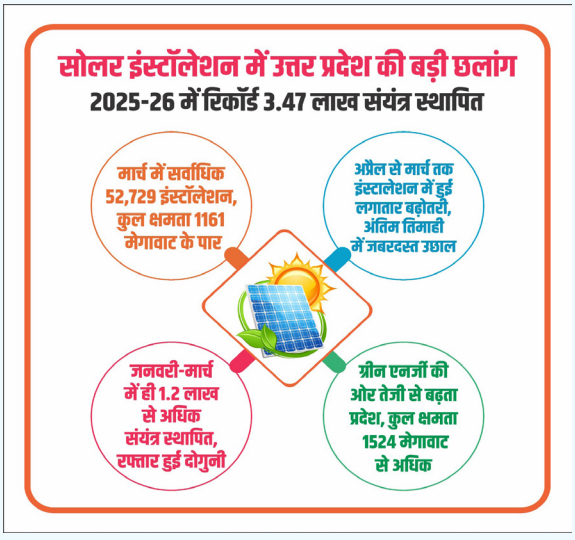

के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और लाइन लॉस को घटाकर लगभग 13.77% तक लाया गया है। साथ ही उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान और नए कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत 2.86 करोड़ से अधिक परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए निजी नलकूप कनेक्शन और मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिससे कृषि क्षेत्र को बड़ा लाभ मिल रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा में उल्लेखनीय प्रगतिः

- नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 27 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि

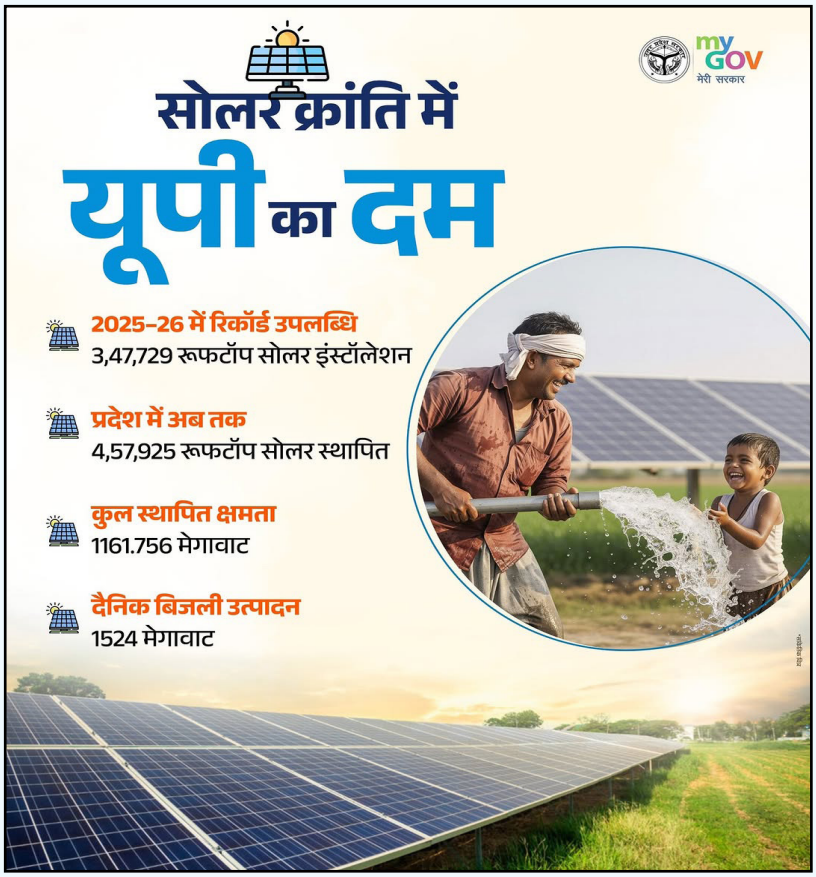

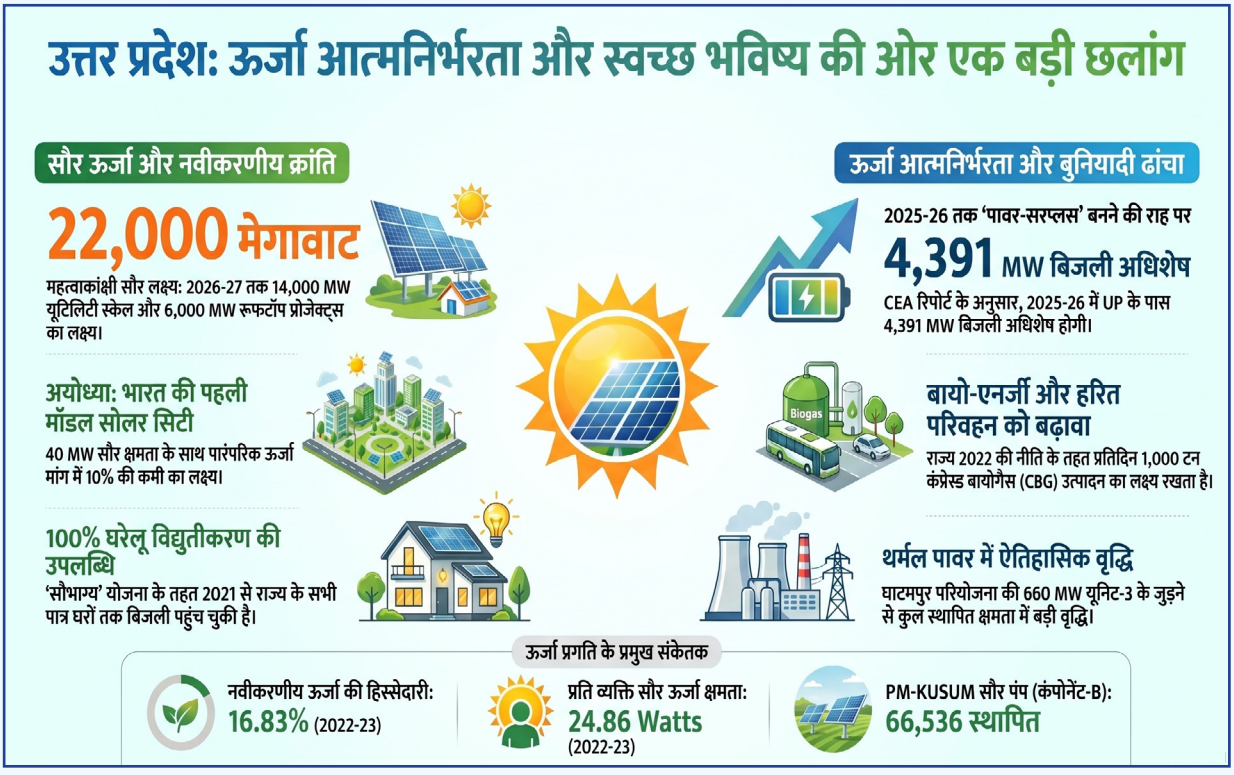

थर्मल ऊर्जा पर लगभग 80 प्रतिशत निर्भरता को कम करते हुए बिजली उत्पादन में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी नवीकरणीय स्रोतों से सुनिश्चित की जाए। यह लक्ष्य प्रदेश को स्वच्छ और सतत ऊर्जा की दिशा में अग्रसर करता है।

- सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। यूटिलिटी स्केल सोलर परियोजनाओं के तहत 2815 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जबकि सरकारी और अर्धसरकारी भवनों पर 202 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2017 से अब तक 2,65,633 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा चुकी हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोशनी पहुंची है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच बढ़ाने के लिए 'सौभाग्य योजना' के तहत दूरस्थ गांवों में 53,354 सोलर पावर पैक स्थापित किए गए हैं, साथ ही डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 17,602 अतिरिक्त सोलर पावर पैक लगाए गए हैं। वहीं पीएम कुसुम योजना के तहत हजारों कृषि पंपों का सोलराइजेशन किया गया है और किसानों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
- अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट, हाईमास्ट, सोलर ट्री, ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क और सोलर आधारित कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही अन्य शहरों में भी सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत व्यापक स्तर पर सौर उपकरण लगाए जा रहे हैं।

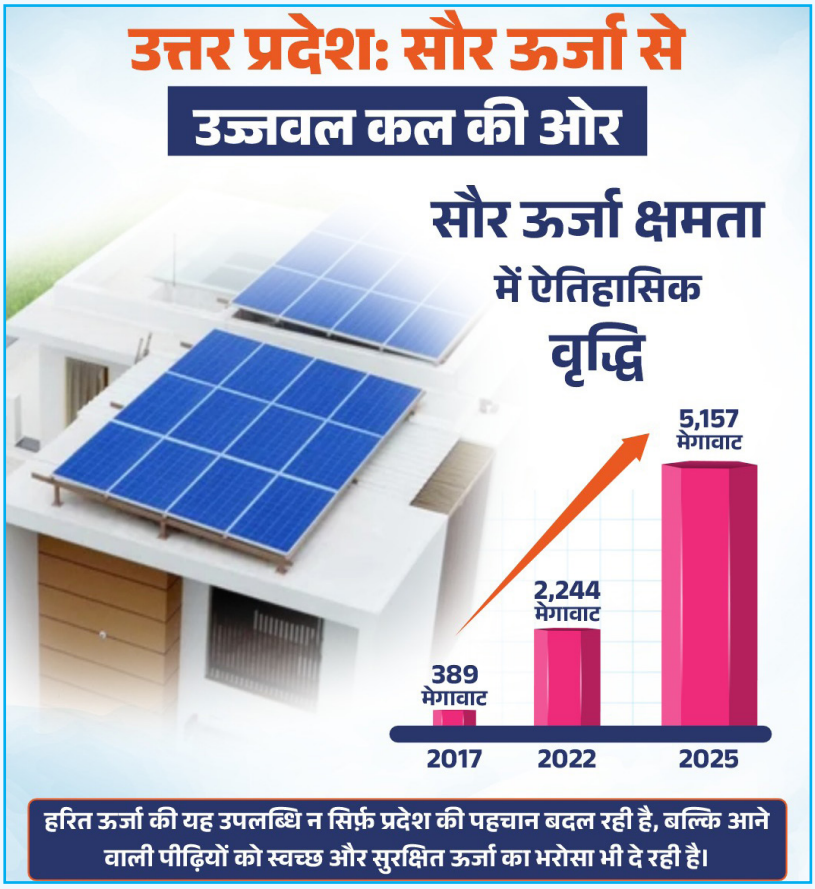

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 14,000 मेगावाट यूटिलिटी स्केल परियोजनाएं, 6,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर और 2,000 मेगावाट पीएम कुसुम योजना के तहत शामिल हैं।
- इसके अलावा, जैव ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि और पशु अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायो-कोल, बायो-डीजल और बायो-एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 62 परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें से 36 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। गोरखपुर में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में भी कार्य कर रहा है। हर जिले में एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित मॉनिटरिंग और मूल्यांकन किया जा रहा है। साथ ही हरित परिवहन और स्वच्छ तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है।
- ऊर्जा क्षेत्र में यह व्यापक परिवर्तन उत्तर प्रदेश को न केवल आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि उसे देश के अग्रणी राज्यों में भी स्थापित कर रहा है। यदि यही गति बनी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश पूरी तरह से ऊर्जा सरप्लस राज्य बनकर देश के विकास में और अधिक योगदान देगा।

लेखक: रामेन्द्र सिंह

जन-जन की ढाल: उत्तर प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा

"विकास का वास्तविक मापदंड वह है, जो अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करे।"

उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार इसी दर्शन को मूर्त रूप देता है। राज्य अब 'वेलफेयर स्टेट' से आगे बढ़कर प्रोएक्टिव, डिजिटल और लक्षित सुरक्षा तंत्र विकसित कर रहा है। आज पेंशन, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास और आजीविकाख्र हर आयाम में समावेशी कवरेज तेजी से बढ़ा है।

बहु–आयामी सुरक्षा जाल का विस्तार

- यदि इसे Multi-Layered Safety Net के रूप में देखें, तो प्रदेश में व्यापक कवरेज दिखाई देता है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के तहत 1.2–1.5 करोड़ लाभार्थियों को DBT के माध्यम से नियमित भुगतान हो रहा है।
- खाद्य सुरक्षा (NFSA) के अंतर्गत 15 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त या सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराया गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50–55 लाख से अधिक घरों का निर्माण/स्वीकृति हुई है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत और राज्य योजनाओं के माध्यम से लगभग 6 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिला है।
- यह समेकित ढांचा गरीबी और आर्थिक झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है।

स्वास्थ्य सुरक्षाः इलाज से वित्तीय सुरक्षा तक

- आयुष्मान भारत–PMJAY के अंतर्गत करोड़ों ई-कार्ड जारी किए गए हैं और लाखों मरीजों को कैशलेस इलाज मिला है।
- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए छूटे हुए परिवारों को भी कवरेज दिया गया है।
- जन औषधि केंद्रों और मुफ्त जांच/दवा योजनाओं से out-of-pocket खर्च में कमी आई है, जिससे गरीब परिवारों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत हुई है।

DBT और पारदर्शिता का प्रभाव

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से पेंशन, छात्रवृत्ति और सब्सिडी सीधे खातों में पहुंचाई जा रही हैं।
- आधार सीडिंग, e-KYC और PFMS जैसी प्रणालियों ने लीकेज कम कर पारदर्शिता बढ़ाई है।
- इससे समयबद्ध भुगतान व प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.7 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन देकर महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान को बढ़ावा मिला है।
- मिशन शक्ति और कन्या योजनाओं के जरिए बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और वित्तीय सहायता मजबूत हुई है।
- NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से लाखों महिलाओं को उद्यमिता और आय सृजन से जोड़ा गया है।

आजीविका और रोजगार सुरक्षा

- मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा था।
- अब 'जी राम जी' 125 दिन रोजगार की गारंटी देता है।
- ODOP (एक जिला, एक उत्पाद) योजना ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर कारीगरों और युवाओं की आय में वृद्धि की है।
- इससे रोजगार, कौशल विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

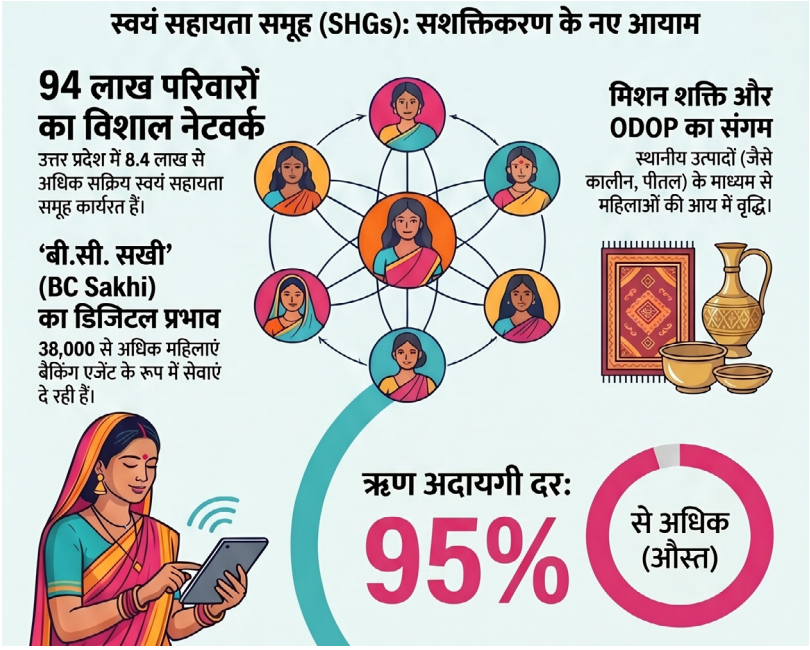

डेटा–ड्रिवन गवर्नेंस

- एकीकृत लाभार्थी डेटाबेस, पोर्टल और ऐप आधारित ट्रैकिंग से योजनाओं की निगरानी मजबूत हुई है।
- सोशल ऑडिट और शिकायत निवारण तंत्र ने घोस्ट/डुप्लिकेट लाभार्थियों में कमी लाई है और लक्षित वितरण को बेहतर बनाया है।

चुनौतियाँ अभी भी मौजूद

- सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं:
  - » शहरी गरीब और प्रवासी मजदूरों का पूर्ण कवरेज
  - » विभिन्न योजनाओं में समन्वय की कमी
  - » क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताएँ
  - » वित्तीय दबाव और दीर्घकालिक फंडिंग
  - » जागरूकता की कमी

सुधार की दिशा में प्रयास

- इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं:
  - » यूनिफाइड सोशल रजिस्ट्री
  - » 'एक देश, एक राशन कार्ड' का विस्तार
  - » योजनाओं का एकीकृत क्रियान्वयन (convergence)
  - » KPI और डैशबोर्ड आधारित मॉनिटरिंग
  - » ग्रीन और डिजिटल रोजगार को बढ़ावा
  - » पंचायत और SHG के माध्यम से जागरूकता

लेखक: रामेन्द्र सिंह

उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांतिः रिकॉर्ड उत्पादन से लेकर चुनौतियों के समाधान तक

उत्तर प्रदेश में बीते 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र ने एक नया मोड़ लिया है। जहाँ एक समय खेती केवल जीवन-यापन का साधन थी, वहीं अब यह एक आधुनिक 'बिजनेस मॉडल' में तब्दील हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश की कृषि विकास दर जो 2016-17 में 8% थी, वह 2025-26 तक 18% पहुँचने का अनुमान है।

गन्ना और एथेनॉलः यूपी बना ऊर्जा का केंद्र

- उत्तर प्रदेश देश में गन्ना उत्पादन का निर्विवाद नेता बना हुआ है। गन्ने की खेती का क्षेत्रफल 20 लाख से बढ़कर 28.6 लाख हेक्टेयर हो गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि एथेनॉल सेक्टर में मिली है, जहाँ उत्पादन 42 करोड़ लीटर से बढ़कर 187.80 करोड़ लीटर पहुँच गया है।
- इससे न केवल किसानों को भुगतान में आसानी हुई है, बल्कि चीनी मिलों की क्षमता बढ़ने से ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं।

प्राकृतिक खेती और डिजिटल मंडियाँ

- पर्यावरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अब 'प्राकृतिक खेती' (Natural Farming) की ओर बढ़ रहा है। बुंदेलखंड के 23,500 हेक्टेयर क्षेत्र के बाद अब इसे 1,886 क्लस्टरों में विस्तार देने की योजना है। साथ ही, 27 नई आधुनिक मंडियों और ई-नाम (e-NAM) प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को बिचौलियों के चंगुल से निकालकर सीधे डिजिटल बाजार से जोड़ा जा रहा है।

बुनियादी ढांचाः नहरों से लेकर नलकूपों तक

- खेती के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में सिंचाई का जाल बिछाया गया है। 76,527 किमी लंबा नहर नेटवर्क और 13 लाख से अधिक नलकूपों ने खेती की तस्वीर बदली है। विशेषकर 'खेत तालाब योजना' ने वर्षा जल संचयन के जरिए सूखे क्षेत्रों के किसानों को एक नई उम्मीद दी है।

वित्तीय सशक्तिकरण और महिला भागीदारी

- किसानों को साहूकारों के कर्ज से

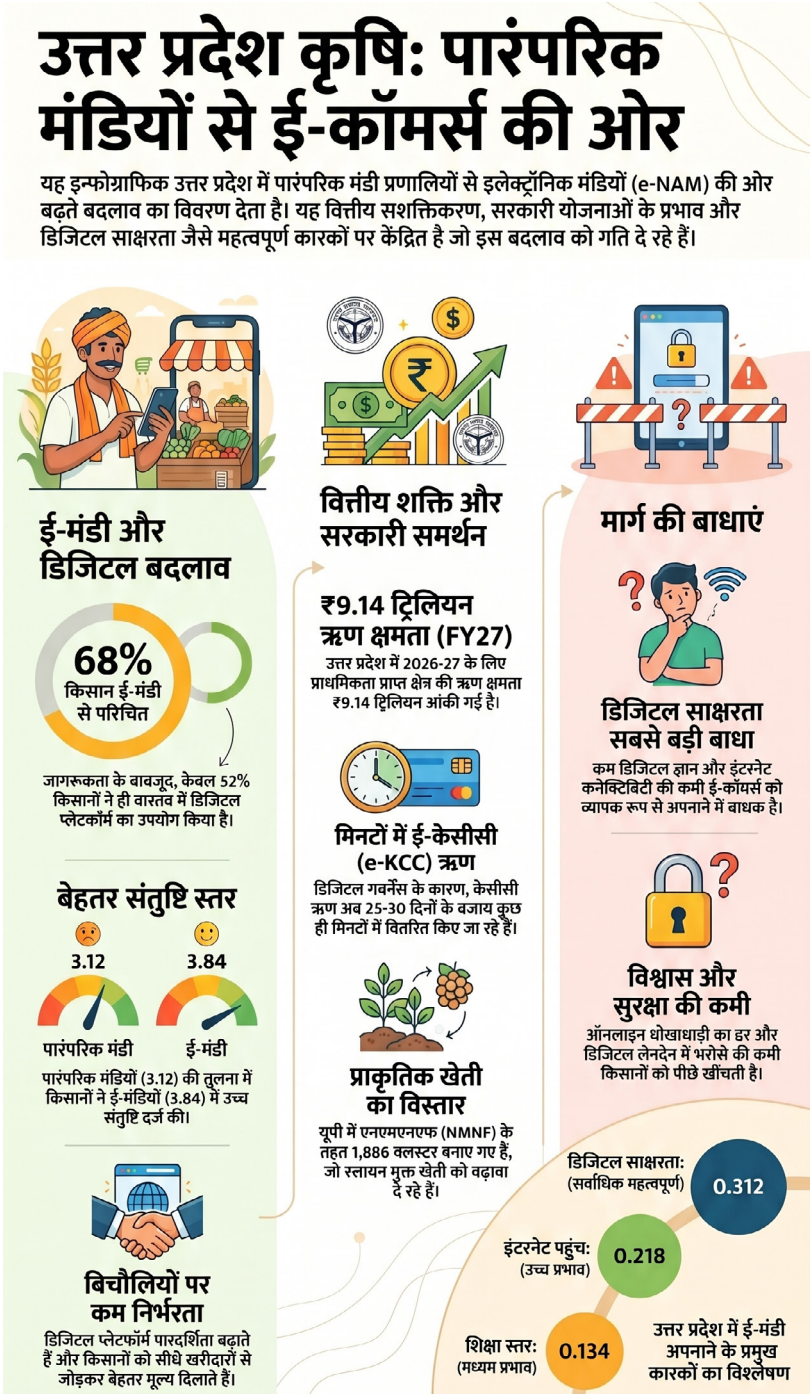

बचाने के लिए 492 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बांटे गए हैं।

- एक दिलचस्प पहलू महिला सशक्तिकरण का भी है, महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा 60 करोड़ के करीब सीडलिंग का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे लगभग 60 हजार ग्रामीण महिलाओं को सीधे रोजगार मिला है।

बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण: निर्यात की नई राह

- यूपी केवल अनाज ही नहीं, बल्कि फलों और सब्जियों में भी नंबर 1 बनने की राह पर है। बागवानी उत्पादन 3.87 करोड़ से बढ़कर 6.03 करोड़ मीट्रिक टन हो गया है। नई 'खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023' के तहत रु.4500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों ने 88,000 से अधिक रोजगार की संभावनाएं पैदा की हैं।

चुनौतियाँ: क्या जमीन पर सब ठीक है?

- रिकॉर्ड उत्पादन के बीच कुछ कड़वे सवाल भी हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए बढ़ती लागत (खाद, डीजल, मजदूरी) एक बड़ी

समस्या है।

- इसके अलावा, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में जल प्रबंधन और डिजिटल मंडियों के बावजूद बिचौलियों का प्रभाव आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। केवल उत्पादन बढ़ना काफी नहीं, असली सफलता तब है जब किसान के मुनाफे (Profit) में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो।

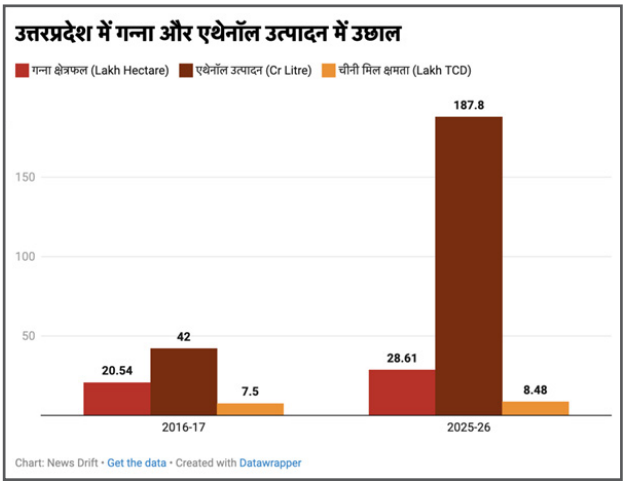

भविष्य की राह: 'आय' केंद्रित नीतियां

News Drift का मानना है कि अब समय केवल उत्पादन के आंकड़ों पर खुश होने का नहीं, बल्कि 'आय' केंद्रित नीतियों पर ध्यान देने का है। जल संरक्षण के लिए माइक्रो-इरिगेशन और स्थानीय स्तर पर योजनाओं का 'ग्राउंड ऑडिट' जरूरी है। अगर तकनीक और बाजार तक सीधी पहुँच को और सुदृढ़ किया गया, तो यूपी का किसान वास्तव में आत्मनिर्भर बनेगा।

लेखक: पंकज द्विवेदी

पलायन प्रदेश से ‘रोजगार प्रदेश’ तक

कभी उत्तर प्रदेश को ‘पलायन प्रदेश’ कहा जाता था, जहाँ के युवा रोजी-रोटी के लिए दिल्ली, मुंबई और सूरत की ओर कूच करते थे। लेकिन मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार के बाद से इस तस्वीर में उल्लेखनीय बदलाव आया है।

युवा रोजगार में वृद्धिः

- राज्य सरकार के आँकड़ों के अनुसार, पिछले 9 वर्षों में 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव से 1 करोड़ 10 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार व सेवायोजन के अवसर बनें।

सरकारी नौकरीः ऐतिहासिक भर्तियों का दौर

- 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रियाएँ अपारदर्शिता, लीक और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात थीं। योगी सरकार ने इस मोर्चे पर क्रांतिकारी बदलाव किए। पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी का सृजन हुआ।
- इन भर्तियों में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अनेक विभाग शामिल हैं। पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न भर्ती बोर्डों द्वारा लाखों युवाओं को सरकारी सेवा का अवसर मिला।
- 2017-25 के दौरान UPSSSC द्वारा 53,011 और UPPSC द्वारा 47,377 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

कौशल विकासः स्किल से रोजगार तक

- रोजगार सृजन का दूसरा बड़ा स्तंभ कौशल विकास है। स्किल इंडिया मिशन और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के माध्यम से प्रदेश में 5 लाख 66 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाया गया है।

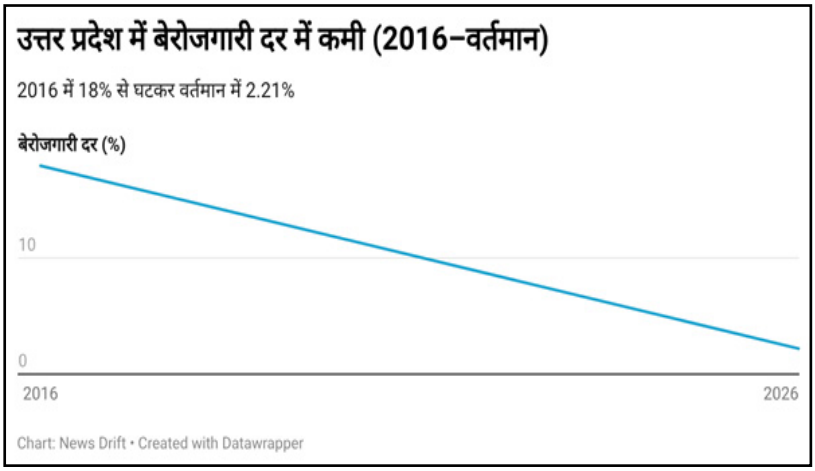

- एक समय रोजगार की तलाश में प्रदेश छोड़ने वाले युवा आज यहीं कौशल प्रशिक्षण लेकर बड़ी कंपनियों में नौकरी पा रहे हैं और स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं।

उद्यमिता और स्टार्टअपः नई उड़ान

- सीएम युवा योजना के माध्यम से प्रदेश में 10 हजार से अधिक इनोवेटिव उद्यम स्थापित किए जा चुके हैं। युवा पारंपरिक व्यवसायों से आगे बढ़कर डिजिटल, AI और ग्रीन-जॉब्स के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। सरकार का विजन 2047 तक उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा स्किल हब बनाना है।

ग्रामीण रोजगारः गाँव में ही मिल रहा काम

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तेज गति से आगे बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 94 नई इकाइयाँ स्थापित हुई हैं, जिनमें रु. 648.63 लाख का पूँजी निवेश हुआ है और 2,586 युवाओं को रोजगार मिला है।
- इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के उद्यमियों को 10 लाख रूपये तक का बैंक ऋण दिया जाता है। सामान्य वर्ग के ऊपर 4% ब्याज सरकार वहन करती है, जबकि आरक्षित वर्ग का पूरा ब्याज राज्य सरकार देती है।
- इसके साथ ही, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के तहत ग्रामीण रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान है और देरी पर मुआवजे का अधिकार भी है।

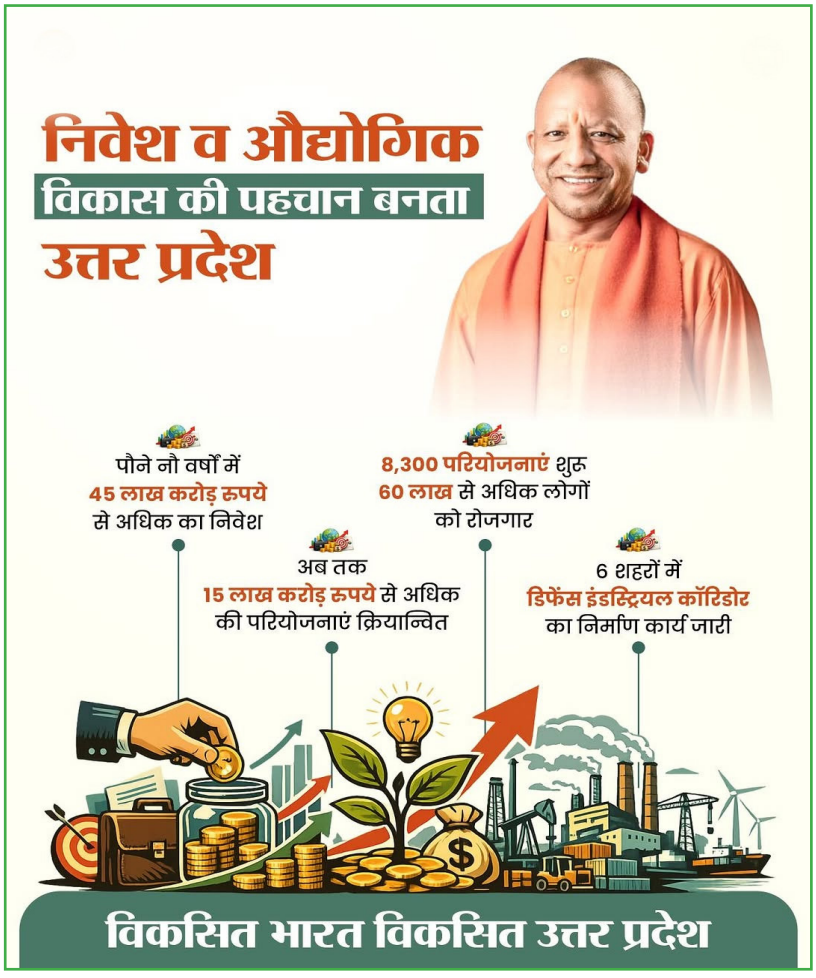

औद्योगिक निवेशः फैक्टरियों की संख्या 17% बढ़ी

- औद्योगिक मोर्चे पर भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रदेश में फैक्टरियों की संख्या 17% बढ़कर 32,000 के पार पहुँच गई है। फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश-विदेश के निवेशकों ने भारी मात्रा में MoU साइन किए।
- 6.77 लाख करोड़ रुपये मूल्य के LOC (लेटर ऑफ कम्फर्ट) स्वीकृत हो चुके हैं। नोएडा के पास नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डेटा सेंटर पार्क (2 लाख करोड़ रूपये निवेश लक्ष्य) और रक्षा औद्योगिक गलियारे जैसी परियोजनाएँ रोजगार के नए द्वार खोल रही हैं।

रोजगार मेलेः डिजिटल कनेक्शन

- प्रदेश में यूपी सेवायोजन विभाग के माध्यम से साल 2025 में 572 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। 2026 में 70 से अधिक जिलों में 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती रोजगार मेलों के जरिये निकाली जा चुकी है।
- लखनऊ, वाराणसी और झाँसी समेत तमाम शहरों में जॉब फेयर आयोजित हो रहे हैं जहाँ निजी कंपनियाँ सीधे युवाओं से साक्षात्कार कर रही हैं।

खेल के साथ रोजगार:

- उत्तर प्रदेश में "एक जनपद, एक खेल" योजना के तहत खिलाड़ियों को रूपये 10 लाख तक पुरस्कार, 75 जनपदों में रूपये 25,000 मासिक प्रशिक्षण, 30 खिलाड़ियों को किट, 789 खिलाड़ियों को सहायता दी गई। स्टेडियम व खेल सुविधाओं के विकास से युवाओं को रोजगार व बेहतर अवसर मिले।

श्रमिक कल्याण: सामाजिक सुरक्षा का नया ढाँचा

- सिर्फ नौकरी नहीं, श्रमिकों के कल्याण पर भी सरकार का ध्यान गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9.52 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं।
- निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज पर 100% खर्च की प्रतिपूर्ति होती है। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत रु.55,000 से रु.61,000 तक की सहायता दी जा रही है।

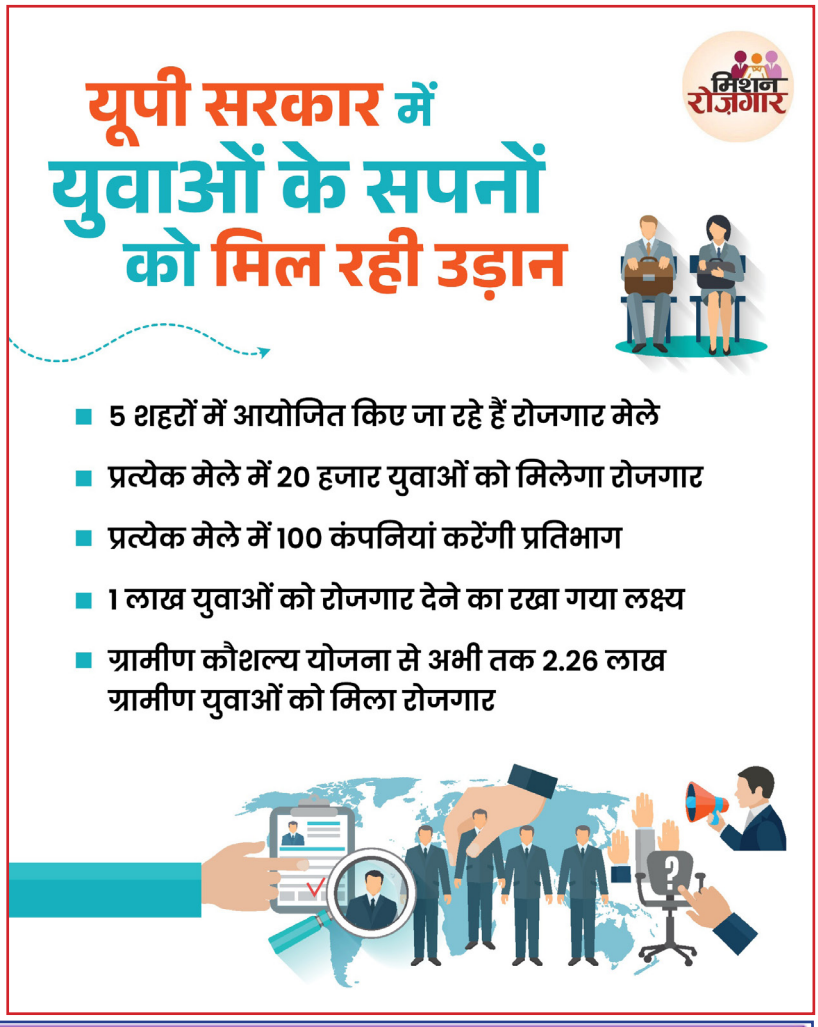

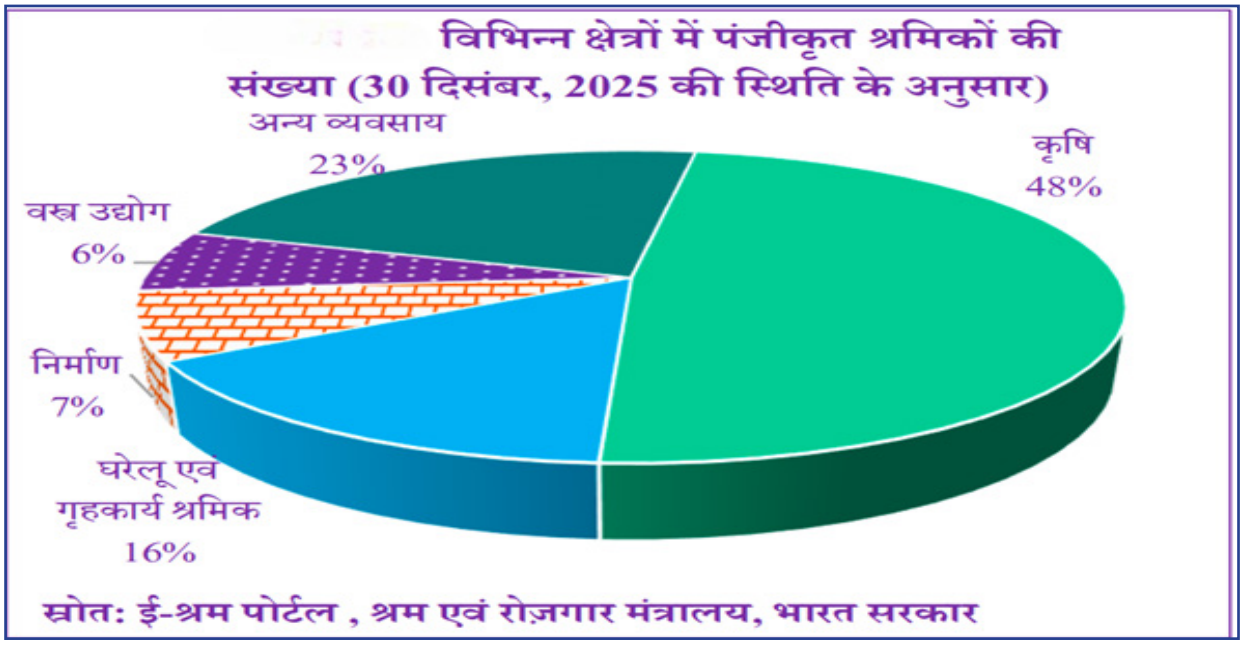

ई–श्रम पंजीकरण में वृद्धिः

- ई-श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले) के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देता है। इस पोर्टल पर आरम्भ से अब तक 8.42 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हुए हैं जिसमे सर्वाधिक पंजीकरण कृषि क्षेत्र में रहा।

उत्तरप्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएंः

योजना का नाम	मुख्य उद्देश्य	उपलब्धियां (अप्रैल 2026 तक)
उत्तरप्रदेश मिशन रोजगार (जुलाई 2025 में गठन)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25000 युवाओं को विदेशों में तथा 300000 अभ्यर्थियों को देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और 400000 अभ्यर्थियों की कॅरिअर कॉउंसलिंग कराने का लक्ष्य निधारित।	▪ लगभग 5978 निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजा जा चुका है। ▪ अगस्त 2025 में इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान , लखनऊ में रोजगार महाकुम्भ का आयोजन जिसमे 16,212 युवाओं का चयन हुआ। ▪ अक्टूबर 2025 में आयोजित इंटरनेशनल प्लेसमेंट इवेंट के माध्यम से 279 अभ्यर्थियों का विदेश में चयन कराया गया। ▪ दिसंबर 2025 में आहूत काशी सांसद रोजगार महाकुम्भ के माध्यम से चयनित 8054 अभ्यार्थियों में से 85 का चयन विदेश में रोजगार के लिए। ▪ वित्तीय वर्ष 2025 में 2,18,848 अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया।
रोजगार मेलों का आयोजन	निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य।	वर्ष 2022 में 1439, वर्ष 2023 में 1907, वर्ष 2024 में 2840 तथा वर्ष 2025 में 3063 मेलों का आयोजन किया गया, जिसमे 10 लाख से अधिक चयन।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA)	युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण	पहले चरण में रु.5 लाख तक का 100% ब्याज मुक्त ऋण।
ODOP (एक जनपद एक उत्पाद)	स्थानीय शिल्प को वैश्विक बनाना	निर्यात रु.88,000 करोड़ (2017) से बढ़कर रु.2.10 लाख करोड़+ (2026)।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)	व्यावसायिक प्रशिक्षण	विगत 9 वर्षों की अवधि में 13.64 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को विभिन्न सेक्टर्स के रोजगारपरक अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया है, जिसमें 12.58 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित हुए हैं तथा 7.67 लाख से अधिक युवा प्रमाणित हो चुके हैं जिनमे से 6.31 लाख को विभिन्न कंपनियों एवं अधिष्ठानों में सेवायोजित कराया गया है।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना	पारंपरिक कारीगरों को टूलकिट और ऋण	1.50 लाख से अधिक कारीगरों को टूलकिट वितरण।
निवेश मित्र – ळठब 2026	औद्योगिक निवेश से रोजगार	रु.15 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर; 10 लाख+ अप्रत्यक्ष रोजगार।

चुनौतियाँः जो अभी बाकी है

- **न्यूनतम वेतन और श्रमिक असंतोषः** अप्रैल 2026 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्रों, विशेषकर नोएडा और गाजियाबाद में बड़े श्रमिक आंदोलनों के साथ हुई। 14 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के

दबाव और बढ़ती महंगाई को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए न्यूनतम वेतन में 21% तक की अंतरिम वृद्धि की घोषणा की। अन्य नगर निगम जिलों के लिए वृद्धि लगभग 14.97 प्रतिशत और अन्य जिलों के लिए लगभग 9.21 प्रतिशत की वृद्धि की है।

- **कौशल का अभाव (Skill Gap):** निवेश तो हाई-टेक क्षेत्रों (आईटी, डिफेंस) में आ रहा है, लेकिन स्थानीय युवाओं के पास उस स्तर का तकनीकी कौशल नहीं है।
- **शिक्षित बेरोजगारी:** उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी एक गंभीर चुनौती है, जहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं में बेरोजगारी दर उच्च (लगभग 17–21% से अधिक) है। राज्य में 15–29 वर्ष के 1 करोड़ से अधिक युवा हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में शिक्षित युवा नौकरी की तलाश में हैं।
- **प्रक्षन्न बेरोजगारी:** उत्तरप्रदेश में 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत है जबकि इस क्षेत्र का राज्य जीडीपी में योगदान 24.9 प्रतिशत ही है, जो इस क्षेत्र में प्रक्षन्न बेरोजगारी को प्रदर्शित करता है।

2017 से 2026 का यह सफर उत्तर प्रदेश के लिए एक परिवर्तनकारी दशक रहा है। सरकारी भर्तियाँ हों, कौशल विकास हो, औद्योगिक निवेश हो या ग्रामीण उद्यमिता– हर मोर्चे पर प्रगति की लकीर खिंची है। अब असली परीक्षा यह है कि क्या यह गति टिकाऊ है और क्या इसका लाभ समाज के सबसे वंचित तबकों तक पहुँच रहा है। यदि सरकार इस दिशा में सुधार जारी रखती है, तो उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था का एक नया इंजन बनकर उभर सकता है।

लेखक: रविकान्त

अपराजिता यूपी: सशक्त नारी, समर्थ प्रदेश

उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की नई इबारत– नीतियाँ, उपलब्धियाँ और शेष चुनौतियाँ

"जब उत्तर प्रदेश की नारी सशक्त होगी, तो प्रदेश स्वतः समर्थ हो जाएगा"– सरकारी दृष्टिकोण, 2017–2026

उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, जहाँ महिलाओं की संख्या 11 करोड़ से अधिक है। वर्ष 2017 से लेकर अप्रैल 2026 तक के नौ वर्षों में इस राज्य ने महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक यात्रा तय की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी हर मोर्चे पर प्रदेश ने नई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। किंतु इस चमकती तस्वीर के पीछे कुछ ऐसी चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें अभी जीतना बाकी है।

नवनिर्माण के 9 वर्ष: एक समग्र दृष्टि

वर्ष 2017 में जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई, तो महिला सशक्तीकरण को सरकारी नीति के केंद्र में रखा गया। 'काम दमदार-जनहितकारी सरकार' की थीम पर तैयार हुई इस रिपोर्टकार्ड में कुछ आँकड़े हैं जो प्रदेश की बदलती तस्वीर को बयान करते हैं।

प्रमुख आँकड़े – महिला सशक्तीकरण (2017–2026)

लखपति दीदी लक्ष्य (2024-25)	35 लाख से अधिक महिलाओं का चिन्हांकन
लखपति श्रेणी में	18.55 लाख से अधिक महिलाएँ
PM मातृ वंदना योजना	60 लाख माताएँ लाभान्वित
BC सखी योजना- वित्तीय लेन-देन	रु.42,711 करोड़ से अधिक
BC सखी- लाभांश अर्जित	रु.116 करोड़
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना	26.81 लाख बेटियाँ लाभान्वित
च्ड स्वनिधि ख्र महिला लाभार्थी	2 लाख से अधिक
UP-112 रिस्पांस टाइम	1 घंटे से घटकर 6 मिनट 41 सेकंड (2025)
UP पुलिस में महिलाएँ	44,000+ (20% आरक्षण)
महिला SHG से जुड़ी महिलाएँ	1 करोड़ से अधिक

आर्थिक सशक्तीकरण: स्वावलंबन की नई राह

- **लखपति महिला योजना:** उत्तर प्रदेश सरकार ने 'लखपति महिला योजना'

के अंतर्गत राज्य में महिलाओं को प्रतिवर्ष रु.1 लाख से अधिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा है। आँकड़ों के अनुसार, 35 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन हो चुका है और 18.55 लाख से अधिक महिलाएँ लखपति की श्रेणी में आ गई हैं। कृषि आजीविका संवर्धन गतिविधियों में 64.34 लाख महिला किसान परिवार अंगीकृत हुए हैं।

- **BC सखी और स्वयं सहायता समूह:** BC सखी योजना (22 मई 2020 को प्रारंभ) के अंतर्गत 39,885 ठब सखियों ने ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ा। इन्होंने रु. 42,711 करोड़ से अधिक का वित्तीय लेन-देन करते हुए रु. 116 करोड़ का लाभांश खुद अर्जित किया। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) के अंतर्गत 9.43 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों ने 64,761 ग्राम संगठनों और 3,296 संकुल स्तरीय संघों का गठन करते हुए 1.06 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ा है। महिला स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 2,682 उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया गया है और 60,000 समूहों की महिलाओं के माध्यम से ड्राई राशन का वितरण किया जा रहा है।
- **PM स्वनिधि और उद्यमिता:** प्रधानमंत्री SVANidhi योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं। 'महिला समर्थ्य योजना' के तहत प्रत्येक SHG को रु. 25,000 का बीज अनुदान, 2% ब्याज सब्वेंशन और कॉमन फैसिलिटी सेंटर तक पहुँच प्रदान की जा रही है। मध्यावधि 2025 तक इस योजना ने 4,500 SHG में 1.2 लाख महिलाओं की आय में औसतन 35% की वृद्धि की है।

शिक्षा और स्वास्थ्य: नींव और भविष्य

- **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना:** 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक रु.25,000 की सहायता 6 चरणों में दी जाती है। अप्रैल 2026 तक 26.81 लाख बेटियाँ इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।
- **स्वास्थ्य सेवाएँ और मातृत्व सहायता:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आँकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में संस्थागत प्रसव दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में SAM (Severely Acute Malnourished) बच्चों की पहचान और प्रबंधन में AMBCs, GMD और AWW तंत्र के माध्यम से 98% efficiency प्राप्त की गई है। 2024-25 तक 1,28,811 से 1,90,065 आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड प्री-स्कूलों में बदलने का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 60 लाख माताएँ लाभान्वित हो चुकी हैं। NFHS-4 और NFHS-5 के बीच तुलना करें तो 0 से 5 वर्ष के बच्चों

में स्टंटिंग दर 7.5% कम हुई है, जबकि 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों में मृत्यु दर में 6.6% की कमी आई है।

सुरक्षा और न्यायः अभय का आश्वासन

सुरक्षा के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश ने 2017 से 2026 के बीच कई ऐतिहासिक बदलाव किए हैं।

महिला सुरक्षा – प्रमुख सुधार (2017–2026)

UP–112 रिस्पांस टाइम	65 मिनट से घटकर 6 मिनट 41 सेकंड (2025)
बलात्कार के मामलों में कमी	33.92% की गिरावट
अपहरण के मामलों में कमी	17.03% की गिरावट
घरेलू हिंसा में कमी	9.54% की गिरावट
UP पुलिस में महिलाएँ	44,000+ (20% पद आरक्षित)
मिशन शक्ति 5.0 (सितम्बर 2025)	नए दिशा–निर्देश, सिंगल–विंडो शिकायत प्रणाली
Operation Garuda	साइबर क्राइम के विरुद्ध विशेष अभियान
Operation Majnu	सार्वजनिक स्थलों पर उत्पीड़न के खिलाफ

मिशन शक्तिः पाँच चरणों की ताकत

- 17 अक्टूबर 2020 को बलरामपुर में शुरू हुआ मिशन शक्ति अभियान अब 5.0 संस्करण में है। सितंबर 2025 में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति 5.0 के नए दिशा–निर्देश जारी किए गए जिसमें एकल–खिड़की शिकायत प्रणाली, समुदाय संवेदीकरण और साइबर अपराध निवारण को प्राथमिकता दी गई है। हर पुलिस स्थानक पर Mission Shakti केंद्र की स्थापना ने महिलाओं को न्याय तक त्वरित पहुँच दिलाई है।
- तीन नई महिला PAC बटालियन का गठन और हर जिले में Anti–Romeo स्क्वाड की तैनाती– ये दो निर्णय यूपी को देश में महिला सुरक्षा के

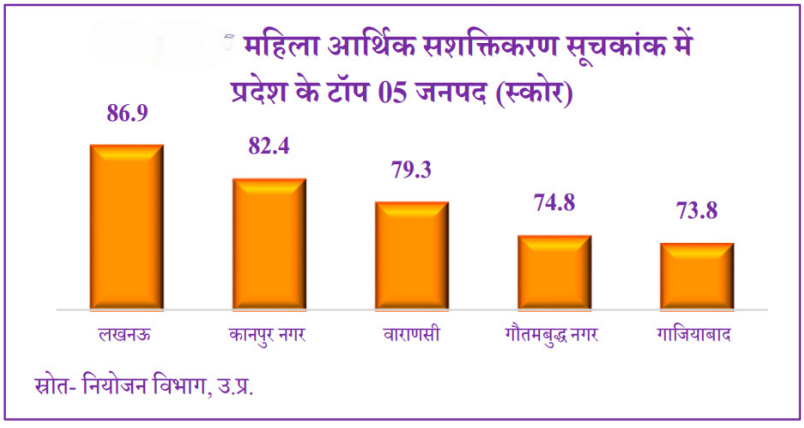

मामले में अग्रणी राज्यों में रखते हैं। 181 महिला हेल्पलाइन अब 24×7 कार्यरत है और 2020-21 से 112 से एकीकृत है।

सामाजिक योजनाएँ: जीवन–चक्र दृष्टिकोण

- **बाल सेवा और विधवा पेंशन:** मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड एवं सामान्य) के तहत 1 लाख 5 हजार बच्चे लाभान्वित हुए हैं। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक बच्चों को उनके अभिभावकों से मिलाया गया। विधवा/निराश्रित महिला पेंशन योजना में 2016-17 में 17.31 लाख लाभार्थियों से बढ़कर अब 28.62 लाख महिलाएँ रु.1,000 प्रतिमाह पेंशन पा रही हैं।
- **मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना:** अक्टूबर 2017 में शुरू इस योजना में 2025 में बड़ा सुधार किया गया ख्र प्रति जोड़े सहायता रु.51,000 से बढ़ाकर रु.1,00,000 कर दी गई और पात्रता की वार्षिक आय सीमा रु.2 लाख से बढ़ाकर रु.3 लाख की गई। अब तक 5.20 लाख बेटियों का विवाह इस योजना के तहत हुआ है।
- **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना:** प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने व जन्म के प्रति जनमानस में सकारात्मक

सोच विकसित करने, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा में वृद्धि के साथ उचित उम्र में विवाह तथा बालिकाओं के प्रति सम्मान में बढ़ोत्तरी।

- **रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष:** जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/ बालिकाओं को तत्काल आर्थिक एवं चिकित्सीय राहत, उनको एवं अवयस्क बच्चों के भरण-पोषण हेतु रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की स्थापना की गयी है। योजना के तहत 2017-18 में लाभार्थियों की संख्या 1606 थी, जो वर्ष 2024-25 में 76.90 % वृद्धि के साथ 2841 हो गयी है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु पात्रता एवं 06 श्रेणियों में देय धनराशि

श्रेणी	श्रेणी विवरण	देय धनराशि	पात्रता शर्तें
प्रथम श्रेणी	जन्म पर	रु. 5000/-	1.उत्तर प्रदेश का निवासी 2.परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रु. 3.00 लाख 3. परिवार में अधिकतम 02 बच्चे ❖ पात्र परिवार को कन्या के नाम से ऑनलाइन आवेदन तथा बैंक खाता खुलवना होता है। ❖ योजनान्तर्गत आच्छादित परिवार की कन्या को विभिन्न स्तरों को पूर्ण करने के सापेक्ष निर्धारित श्रेणीवार धनराशि सीधे उसके खाते में हस्तांतरित की जाती है।
द्वितीय श्रेणी	एक वर्ष तक का टीकाकरण पूर्ण होने पर	रु. 2000/-	
तृतीय श्रेणी	कक्षा-1 में प्रवेश पर	रु. 3000/-	
चतुर्थ श्रेणी	कक्षा-6 में प्रवेश पर	रु. 3000/-	
पंचम श्रेणी	कक्षा-9 में प्रवेश पर	रु. 5000/-	
षष्टम श्रेणी	कक्षा-10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश पर	रु. 7000/-	
कुल		रु. 25000/-	

WEE Index: डेटा–आधारित शासन की दिशा में

- 2025 में उत्तर प्रदेश की योजना विभाग ने न्कंपजप थ्वनदकंजपवद के सहयोग से महिला आर्थिक सशक्तीकरण (WEE) सूचकांक तैयार किया। यह सूचकांक 75 जिलों में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक

और शैक्षणिक स्थिति को ट्रैक करता है। मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम में इसकी रियल-टाइम मॉनिटरिंग प्रदेश में लैंगिक नीति निर्माण को नई दिशा दे रही है।

- यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में केवल 46% महिलाएँ मोबाइल फोन का उपयोग करती हैं और इंटरनेट साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। ऐसे में लैंगिक डेटा का व्यवस्थित संग्रह नीतिगत खामियों को दूर करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

*''प्रदेश 2027 तक **$1** ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लेकर चल रहा है- और यह लक्ष्य महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है।''*

चुनौतियाँ: जिन्हें अभी जीतना बाकी है

उपलब्धियों की लंबी सूची के बावजूद, उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की राह में कई गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं-

चुनौती का क्षेत्र	विवरण
डिजिटल असमानता	केवल 46% महिलाएँ मोबाइल उपयोगकर्ता; इंटरनेट साक्षरता राष्ट्रीय औसत से नीचे। डिजिटल योजनाओं का लाभ बड़े वर्ग तक नहीं पहुँचता।
श्रम शक्ति भागीदारी	NFHS-5 के अनुसार UP में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर राष्ट्रीय औसत से कम। कृषि के बाहर फॉर्मल रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी बेहद कम।
ग्रामीण-शहरी विभाजन	योजनाओं का लाभ मुख्यत: अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक सीमित। दूरदराज के जिलों में क्रियान्वयन की खाई अभी पाटनी बाकी है।
कुपोषण	NFHS-5 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 32% बच्चे अभी भी कम वजन के हैं। महिलाओं में एनीमिया की दर चिंताजनक है।
बाल विवाह	सरकारी प्रयासों के बावजूद ग्रामीण UP के कुछ जिलों में बाल विवाह की प्रथा जारी है। जागरूकता अभियानों का असर असमान है।
साइबर अपराध	महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रही है। Operation Garuda जैसे प्रयास जारी हैं लेकिन साइबर फोरेंसिक क्षमता सीमित है।

संपत्ति और विरासत अधिकार	कानूनी प्रावधानों के बावजूद जमीन और संपत्ति पर महिलाओं का वास्तविक नियंत्रण सीमित है।
डेटा की कमी	लैंगिक आधार पर बँटे हुए आँकड़ों का अभाव नीति निर्माण में बाधा बनता है। WEE Index इस दिशा में पहला कदम है लेकिन अभी पूर्ण एकीकरण बाकी है।

आगे की राहः 'अपराजिता' की संभावनाएँ

- 'अपराजिता'– जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। यह शीर्षक उत्तर प्रदेश की उस नारी के लिए है जो कभी हाशिये पर थी, पर आज बदलाव की अग्रदूत है। WEE Indes, Mission Shakti 5.0, लखपति दीदी कार्यक्रम और BC सखी नेटवर्क– ये सभी एक व्यापक तंत्र के हिस्से हैं जो महिला सशक्तीकरण को 'योजना' से 'आंदोलन' में बदल रहे हैं।
- आनेवाले वर्षों में जिन क्षेत्रों पर ध्यान आवश्यक है, वे इस प्रकार हैं:–
  - » **डिजिटल साक्षरता को प्राथमिकताः** हर SHG महिला को स्मार्टफोन और इंटरनेट से जोड़ना।
  - » **फॉर्मल रोजगारः** ODOP और MSME के माध्यम से महिलाओं के लिए शहरी और अर्ध–शहरी रोजगार सृजन।
  - » **स्वास्थ्य निवेशः** आंगनवाड़ी केंद्रों का पूर्ण प्री–स्कूल रूपांतरण और एनीमिया उन्मूलन अभियान।
  - » **न्यायिक त्वरणः** महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में त्वरित सुनवाई हेतु फास्ट–ट्रैक कोर्टों का विस्तार।
  - » **जेंडर बजटिंगः** हर विभाग में लैंगिक आवंटन का पारदर्शी ऑडिट और WEE Index का अनिवार्य उपयोग।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में नौ वर्षों की यह यात्रा यह सिद्ध करती है कि जब नीतियाँ महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं, तो परिणाम दिखते हैं। 60 लाख मातृ वंदना लाभार्थियों से लेकर 44,000 महिला पुलिसकर्मियों तक, 26 लाख कन्या सुमंगला बेटियों से लेकर 18.55 लाख लखपति दीदियों तक – यह संख्याएँ महज आँकड़े नहीं, ये उत्तर प्रदेश की अपराजिता नारी की ताकत की गवाही हैं। लेकिन 'अपराजिता' की कहानी तब पूरी होगी जब प्रदेश की आखिरी महिला 'चाहे वह बुंदेलखंड के किसी सूखाग्रस्त गाँव में हो या पूर्वांचल के दूरदराज के टोले में', भी इन योजनाओं का वास्तविक लाभ पाए।

लेखकः श्वेता शुक्ला

एक समय था जब उत्तर प्रदेश का नाम लेते ही दिमाग में आता था- बाहुबली नेता, माफिया राज, दंगे, दहशत और लाचार पुलिस। 2017 से पहले का UP ऐसा ही था। लेकिन 2026 का UP कुछ और कहानी कहता है।

जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभाला, तब उत्तर प्रदेश में केवल 1.5 लाख पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि स्वीकृत पद थे 3 लाख। पिछली SP और BSP सरकारों ने न सिर्फ पुलिस बल को कमजोर छोड़ा, बल्कि राजनीतिक संरक्षण में माफिया को पनपने दिया। 'लड़के हैं, गलती हो जाती है' जैसे बयान उस युग की मानसिकता को बयान करते हैं।

2017 से पहले का यूपी: 'गुंडाराज' की इबारत

- 2016 में SP शासन के अंतिम वर्ष में उत्तर प्रदेश के आँकड़े भयावह थे। तत्कालीन आँकड़ों के अनुसार 2016 के मुकाबले 2025 तक अपराधों में उल्लेखनीय कमी आयी है, हत्या के मामलों में 47% की गिरावट आई, डकैती में 90% और लूट में 85%, फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में 62 प्रतिशत, दहेज हत्या में 19 प्रतिशत, बलात्कार के घटना में 53 प्रतिशत की कमी आई है-ये संख्याएँ खुद बताती हैं कि पहले और अब के उत्तर प्रदेश में क्या फर्क है।
- 1990 के दशक से ही SP और BSP अपनी चुनावी जरूरतों के लिए बाहुबलियों पर निर्भर हो गई थीं। 1996 में सपा ने इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के अतीक अहमद को विधानसभा टिकट दिया, तो बसपा

ने मऊ से मुख्तार अंसारी को। इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला, इन्होंने जमीनें हड़पीं, हत्याएँ करवाईं, चुनावों में बूथ कैप्चर किए।

'अतीक अहमद ने एक बार अपने घर पर कई पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 जजों ने उनकी जमानत सुनने से इनकार कर दिया था।' - समकालीन मीडिया रिपोर्ट्स, 2000-2010

- मुख्तार अंसारी ने 2005 में जेल में रहते हुए BJP विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करवाई। DSP शैलेंद्र सिंह ने जब मुख्तार के खिलाफ POTA में मुकदमा किया, तो मुलायम सरकार ने उन पर दबाव बनाया और अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में थे, फिर भी 2017 तक एक बार भी सजायाफ्ता नहीं हुए, राजनीतिक रसूख और गवाह-पक्षाघात का यही खेल था।

"हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।"

— मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, UP विधानसभा में

माफिया राज का अंतः

- अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 2017 के बाद UP पुलिस को 'फ्री हैंड' दिया

अतीक अहमद
माफिया-नेता | प्रयागराज

- 5 बार MLA, 1 बार MP — SP का संरक्षण
- हत्या, अपहरण, जमीन कब्ज़ा के 100+ मुकदमे
- 1995 गेस्टहाउस कांड में मायावती पर हमले का आरोप
- 2005 में MLA राजू पाल की हत्या का आरोप
- योगी सरकार ने ₹1,400 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की
- बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया

✅ 2023 में पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या, माफिया साम्राज्य ध्वस्त

मुख्तार अंसारी
माफिया-नेता | मऊ / गाज़ीपुर

- 27 साल तक मऊ से MLA — BSP/SP का साया
- 66 आपराधिक मुकदमे, 2005 से जेल में
- BJP MLA कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप
- पूर्वांचल में वसूली, जमीन और ठेकेदारी का नियंत्रण
- 2017 तक एक भी बार सज़ायाफ्ता नहीं
- योगी सरकार में 8 बार सज़ायाफ्ता हुए

✅ 2024 में जेल में मृत्यु, 32 साल पुराने हत्या मामले में उम्रकैद मिली

विकास दुबे
गैंगस्टर | कानपुर

- कानपुर में 60+ गंभीर मुकदमे
- 2020 में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या — बिकरू कांड
- पुलिस को अंबुश में फँसाया
- कई राज्यों में भागा, मध्यप्रदेश में पकड़ाया
- गिरोह का पूरा नेटवर्क ध्वस्त

✅ जुलाई 2020 एनकाउंटर में खात्मा, घर बुलडोज़र से ज़मीनदोज़

अन्य प्रमुख कार्रवाइयाँ
Land Mafia | Sand Mafia | Extortion

- 68 बड़े माफियाओं पर 700+ FIR, ₹4,000+ Cr संपत्ति ध्वस्त
- 350+ हथियार लाइसेंस रद्द
- Anti-Land Mafia Portal: 3,41,236 शिकायत में 68,841 हेक्टेयर मुक्त
- NSA में 924 से अधिक गिरफ्तारियाँ
- 95% Atiq-Mukhtar गैंग सदस्य — मृत, जेल या फरार

✅ बुलडोज़र जस्टिस — गरीबों की ज़मीन वापसी का प्रतीक

गया। नतीजे ऐतिहासिक रहे। 2017 से अब तक 267 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए एवं 10990 घायल हुए। 22306 इनामी अपराधियों को जेल भेजा गया और 85118 अपराधियों के विरुद्ध गैंस्टर अधिनियम तथा 977 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए (NSA) की कार्यवाही हुई।

- गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मार्च 2017 से दिसंबर 2025 तक रुपये 14580 करोड़ से अधिक मूल्य की चल-अचल अवैद्य सम्पत्तियाँ जब्त की गयी और चिन्हित माफिया गैंग के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए 35 माफिया, 94 सह अपराधियों को अलग अलग आजीवन कारावास की सजा दिलायी गयी है। दो को मृत्यदंड की सजा दिलाई गयी है।

सुरक्षित संरचना:

- प्रदेश में सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए 134 नए थाने, 86 नई पुलिस चौकी, 78 महिला पुलिस चौकी परामर्श केंद्र, 75 विद्युत निरोधक पुलिस थाना, 10 सतर्कता अधिष्ठान थाना, 04 आर्थिक अपराध इकाई थाने, 73 साइबर क्राइम थाने व 06 नए नारकोटिक्स थानों की स्थापना की गयी। मानव तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 75 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों में परिवर्तित किये गए।

सुगम व्यवस्था:

- यूपी 112 द्वारा 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कॉल अटेंड की गयी और यूपी 112 में साइबर हेल्पलाइन डेस्क की शुरुवात 28 मई 2021 को की गई जिससे 7,52,422 सूचनाएं प्राप्त हुई।
- वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2025 में अभूतपूर्व सुधार करते हुए यूपी 112 का रिस्पांस टाइम 1 घंटा 5 मिनट से घटकर 06 मिनट 41 सेकेंड किया गया।

सरकार के कदम: नीतियाँ और पहलें

केवल मुठभेड़ और बुलडोजर तक सीमित नहीं रही योगी सरकार- व्यापक नीतिगत सुधार और तकनीकी आधुनिकीकरण ने भी बड़ा रोल निभाया।

- **UP-112 और तकनीकी एकीकरण:** औद्योगिक हब और आवासीय परिसरों में लगे सुरक्षा अलार्म सिस्टम को UP-112 कमांड सेंटर से जोड़ा गया। घटना होने पर तत्काल अलर्ट और समन्वित कार्रवाई संभव हुई।

- **मिशन शक्ति (महिला सुरक्षा):** अक्टूबर 2020 में लॉन्च, अब तक 5 चरण पूरे। 9 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुँच। वीमेन पावर लाइन 1090 ने 7.78 लाख मामले सुलझाए। वन स्टॉप सेंटर ने 2.10 लाख हिंसा पीड़ितों को राहत दी। एंटी रोमियो स्कवॉड कॉलेजों, बाजारों, बस अड्डों पर तैनात। मिशन शक्ति 5.0 (सितम्बर 2025) में ऑपरेशन गरुड़ (साइबर अपराध) ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, ऑपरेशन बचपन, ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन डायल, ऑपरेशन रक्षा सफलतापूर्वक संचालित हुए। ITSSO पोर्टल के अनुसार महिला एवं बाल अपराधों के निस्तारण में 98.90 प्रतिशत के साथ उत्तरप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा।
- **Anti-Land Mafia Portal:** 3,41,236 शिकायतें मिलीं, 3,39,552 निस्तारित। 68,841 हेक्टेयर अवैध कब्जे से मुक्त। 776 जमीन माफिया चिन्हित, 189 जेल में।
- **NCRB 2023 में UP की रैंकिंग:** 181.3 अपराध प्रति लाख–राष्ट्रीय औसत 270.3 से काफी नीचे। हत्या दर 1.4, डकैती दर 0.03, लूट दर 0.6, इन मानकों पर UP राष्ट्रीय औसत से बेहतर। प्रदेश अब 28 राज्यों में 20वें स्थान पर, अर्थात 7 साल में ऊपर से नीचे की तरफ आया।
- **ऑपरेशन कन्विक्शन:** इसके अंतर्गत 1 जुलाई 2023 से 28 दिसंबर 2025 तक कुल 1,25,985 अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया और 79 अभियुक्तों को मृत्युदंड और 10 हजार 414 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई।
- **एसटीएफ और एटीएस:** एसटीएफ ने मार्च 2017 से अब तक 7627 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 75 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया। वहीँ एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) ने 148 आतंकवादी गिरफ्तार किये और 186 रोहिंग्या बांग्लादेशी, पाकिस्तानी व अन्य अवैद्य रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की।

- **भ्रष्टाचार निवारण संगठन:** परिक्षेत्रीय स्तर पर 8 नई इकाइयों का सृजन किया गया। जिसके तहत वर्ष 2022 से अब तक विभिन्न विभागों के खिलाफ 999 सफल ट्रैप, रुपये 1 करोड़ 26 लाख से अधिक बरामदी और 2081 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाई हुई।
- **एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ):** एएनटीएफ द्वारा वर्ष 2025 में 120 अभियोग के अंतर्गत 337 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और 12,810 किग्रा से अधिक मादक पदार्थ बरामद किये गए और ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत 12,61,495 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया गया।
- **कवच योजना:** इण्डो–नेपाल बॉर्डर एवं सीमावर्ती जनपदों में प्रभावी सुरक्षा हेतु कवच योजना के तहत उत्तरप्रदेश के नेपाल सीमा पर स्थित 07 जनपदों के 570 किमी क्षेत्र में SSB के साथ संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है।
- **प्रभावी पुलिसिंग के लिए तकनीकी उन्नयन:** वर्ष 2025 में लॉन्च यक्ष एप से अपराधियों का डिजिटल रिकॉर्ड और सत्यापन मजबूत हुआ। UPCOP व प्रहरी एप के जरिए ऑनलाइन FIR सहित 27 सेवाएं उपलब्ध हैं, 50 लाख डाउनलोड और 2.10 करोड़ से अधिक FIR दर्ज। चरित्र सत्यापन समय घटकर 6 दिन हुआ। Crime Analytics Portal को FICCI अवार्ड मिला और DQI में पुलिस शीर्ष पर

रही।

अभी भी बाकी हैं चुनौतियाँ

उपलब्धियाँ असंदिग्ध हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह भी है कि चुनौतियाँ अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। एक संतुलित समीक्षा के लिए इन्हें भी देखना जरूरी है।

- **एनकाउंटर की विश्वसनीयता पर सवाल:** इलाहाबाद हाईकोर्ट और मानवाधिकार संगठनों ने कुछ एनकाउंटर की जाँच की माँग की है। Gangster Act के दुरुपयोग पर भी अदालत ने टिप्पणी की है। न्यायिक प्रक्रिया की जगह पुलिसिया कार्रवाई को वैधता देने का विमर्श जारी है।
- **महिला अपराध के आँकड़े चिंताजनक:** NCRB 2023 में UP में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर 58.6 प्रति लाख महिला जनसंख्या दर्ज हुई। रेप, दहेज हत्या और घरेलू हिंसा के मामले राष्ट्रीय सुर्खियाँ बनते रहते हैं। हाथरस (2020) और उन्नाव जैसे मामले राज्य की छवि को झटका देते हैं।
- **साइबर अपराध में तेज बढ़ोतरी:** NCRB 2021 में UP साइबर अपराध में देश में दूसरे स्थान पर था (8,829 मामले)। ऑनलाइन फ्रॉड, धोखाधड़ी और डिजिटल जासूसी में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हो रही है। Cyber थाने और थ्वतमदेपब स्ंे अभी पर्याप्त नहीं हैं।
- **रेत/खनन माफिया अभी भी सक्रिय:** यमुना, बेतवा और अन्य नदियों में अवैध रेत खनन जारी है। 2018 और 2024 में पत्रकारों की हत्या रेत माफिया की दबंगई का प्रमाण है। माफिया-नेता-अधिकारी गठजोड़ अभी पूरी तरह टूटा नहीं है।
- **कथित राजनीतिक पक्षपात का आरोप:** विपक्ष का आरोप है कि Gangster Act और बुलडोजर का उपयोग कभी-कभी विरोधी नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की तरह किया जाता है। इस पर न्यायपालिका ने भी चिंता जताई है।
- **नोएडा श्रमिक असंतोष (2026):** अप्रैल 2026 में नोएडा में 42,000 से अधिक मजदूरों का विरोध-प्रदर्शन औद्योगिक क्षेत्र में श्रम अशांति और कानून-व्यवस्था के नए आयाम की ओर इशारा करता है। इस आंदोलन के असंतोष और हिंसक प्रदर्शनों में पाकिस्तान से संचालित सोशल मीडिया हैंडल्स की भूमिका सामने आई है। यूपी सरकार और पुलिस जांच के अनुसार, यह श्रमिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी।

सरकार के कदमों की समीक्षा:

निष्पक्ष समीक्षा यह कहती है कि UP सरकार ने जो हासिल किया, वह ऐतिहासिक है, लेकिन जिस तरह से हासिल किया, उस पर बहस जारी रहनी चाहिए।

- **माफिया की संस्थागत जड़ें खत्म:** अतीक-मुख्तार जैसे बाहुबलियों की सजा यह साबित करती है कि 'कोई भी कानून से ऊपर नहीं।' दशकों से लंबित मुकदमों में सजा दिलाना, यह न्याय व्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है।
- **गरीबों को जमीन वापसी:** 68,841 हेक्टेयर भूमि माफिया से मुक्त कराई गई। यह उन गरीब किसानों और दलितों के लिए राहत है जिनकी जमीन दशकों से बाहुबलियों ने हड़प रखी थी।
- **निवेश का माहौल बना:** पूर्वांचल जैसे इलाके, जो कभी माफिया के गढ़ थे, अब निवेश आकर्षित कर रहे हैं। कानून-व्यवस्था सुधार का सीधा असर उद्योगों की आमद पर पड़ा है।
- **कानूनी प्रक्रिया की अनिवार्यता:** सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बुलडोजर जस्टिस पर लगाम लगाई और स्पष्ट किया कि 'किसी आरोपी की संपत्ति बगैर कानूनी नोटिस के नहीं गिराई जा सकती।' कार्यपालिका को न्यायपालिका की सीमा का सम्मान करना होगा।
- **Cyber और Women Crime पर फोकस:** साइबर अपराध और महिला सुरक्षा के मामलों में तत्परता और संवेदनशीलता बढ़ानी होगी। Mission Shakti 5.0 सही दिशा में है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की गति और बढ़े।

FY26 बजट में पुलिस के लिए रु.2,250 करोड़ का आवंटन अच्छा संकेत है। Cyber Forensic Labs, Body Cameras और Community Policing को और विस्तार मिलना चाहिए ताकि 'भयमुक्त UP' का दावा डेटा-समर्थित बना रहे।

लेखक: रवि कान्त

थल, जल, नभः उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व कनेक्टिविटी क्रांति

उत्तर प्रदेश– 25 करोड़ की आबादी, 80 जिले और विविधता से भरा भूगोल। 2017 से पहले यह राज्य कनेक्टिविटी की दृष्टि से देश में पिछड़ा हुआ था।पूर्वांचल की यात्रा 15 घंटे में होती थी, बुन्देलखण्ड की पहचान ही पिछड़ेपन से थी और ज्यादातर जिलों में कोई हवाई संपर्क नहीं था। लेकिन पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश ने एक ऐसीकनेक्टिविटी क्रांति लिखी है जो देश की किसी भी राज्य सरकार ने नहीं लिखी।

एक्सप्रेसवे	लंबाई	स्थिति	विशेषता
यमुना एक्सप्रेसवे	165 km	✅ चालू	UP का पहला, नोएडा–आगरा
आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे	302 km	✅ चालू	6-लेन, यात्रा समय 6h→3.5h
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे	340 km	✅ चालू (2021)	लखनऊ–गाज़ीपुर, 15h→5h
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे	296 km	✅ चालू (2022)	28 महीने में निर्मित, रिकॉर्ड
दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे	96 km	✅ चालू	14 लेन, भारत का चौड़ा राजमार्ग
गंगा एक्सप्रेसवे	594 km	🔶 लगभग पूर्ण	मेरठ–प्रयागराज, देश में 2nd सबसे लंबा
गोरखपुर–शामली एक्सप्रेसवे	700 km	🔶 प्रस्तावित	UP का सबसे लंबा, 22 ज़िले

थलः एक्सप्रेसवे की राजधानी –भारत में वर्चस्व

उत्तरप्रदेश में 19 किमी प्रतिदिन की औसत से मार्गों का नवनिर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।

- 4,400+किलोमीटर के एक्सप्रेसवे नेटवर्क के साथ उत्तर प्रदेश आज भारत का निर्विवाद 'Expressway Capital' है। देश के शीर्ष 10 सबसे लंबे एक्सप्रेसवेज में से 4 अकेले UP में हैं और जैसे ही Ganga Expressway पूर्ण होगा, यह संख्या 5 हो जाएगी। 22 एक्सप्रेसवे (चालू और निर्माणाधीन) UP के हर कोने को जोड़ने का काम कर रहे हैं।
- गंगा एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इसमें 3.5 किमी की एयरस्ट्रिप शाहजहाँपुर के जलालाबाद क्षेत्र में बनाई गई है, जो लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए उपयुक्त है। यह सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर में रक्षा–एकीकरण का अनूठा उदाहरण है। साथ ही यह Meerut को Prayagraj से जोड़ते हुए 518 गाँवों से गुजरेगा और 12 जिलों को विकास की मुख्यधारा में लाएगा।
- **राज्य मार्गों का विस्तार:** 5604 किमी के मार्गों का श्रेणी परिवर्तन करते हुए 70 नए राज्यमार्ग घोषित किये गए। रुपये 7000 करोड़ की लागत से राजधानी लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर का विकास किया गया।

- **ग्रामीण मार्ग:** वर्तमान सरकार अब तक के कार्यकाल में लगभग 35,433 किमी लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण कर चुकी है।

परिवहन तंत्र को सशक्त करने संबंधी मुख्य पहल

- **आधार प्रमाणीकरण आधारित ऑनलाइन डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन योजना** लागू।
- सेन्ट्रलाइज **स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स** निर्गमन का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- देश का प्रथम राज्य जहाँ **मोबाइल ऐप आधारित ई-चालान** व्यवस्था शुरू हुई।
- फरवरी 2022 से **वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्रों** हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ; **दिसम्बर, 2025 तक 84 केन्द्र मान्यता प्राप्त, जिनमें 45 केन्द्र क्रियाशील।**
- **नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा**: पुराने वाहन का पंजीयन चिन्ह नए वाहन पर पोर्ट करने की व्यवस्था।
- **वेब-आधारित वाहन 4.0 प्लेटफॉर्म**: **'वन नेशन-वनआरटीओ'** पूरे देश की वाहन पंजीयन व्यवस्था के लिए एकीकृत वेब प्लेटफॉर्म।
- **डिजिटल भुगतान को बढ़ावा**: नगरीय परिवहन बसों में **'वन यूपी वन कार्ड'** कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत।
- वाहनों की फिटनेस जाँच के लिए **ऑनलाइन फिटनेस व्यवस्था लागू।**

रेलवे नेटवर्क:

- UP में लगभग 16000 किमी का रेलवे नेटवर्क है जो देश में सबसे बड़ा है। 5 रेलवे जोन इस राज्य से गुजरते हैं। Western और Eastern Dedicated Freight Corridor (DFC) का संगम UP के दादरी में होता है, जो राज्य को मुंबई के JNPT और कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह, दोनों से जोड़ता है।
- **मेट्रो और आरआरटीएस:** लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा (एक्वा लाइन), चार शहरों में मेट्रो सेवाएं चालू हैं। प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो प्रस्तावित है। सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस (नमो भारत) फरवरी 2026 में पूर्ण 82.15 किमी पर शुरू हो गई। 180 किमी/घंटे की डिजाइन स्पीड, हर 5-15 मिनट पर ट्रेन, यह यूपी को देश के पहले सेमी हाई-स्पीड कम्यूटर रेल सिस्टम का गौरव दिलाती है।

नभः 21 हवाई अड्डे – देश का पहला राज्य

- 2014 में UP में केवल 6 हवाई अड्डे थे। 2026 में यह संख्या 21 है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास 20 से अधिक हवाई अड्डे हैं। 16 ऑपरेशनल, 5 निर्माणाधीन।
- जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस सूची का केंद्रबिंदु है। 28 मार्च 2026 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता है, लेकिन पूरी तरह विकसित होने पर यह विश्व के चार सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल होगा। यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस और दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल सब इसे जोड़ेंगे। पास

भारत में UP का वर्चस्व: इन्फ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग

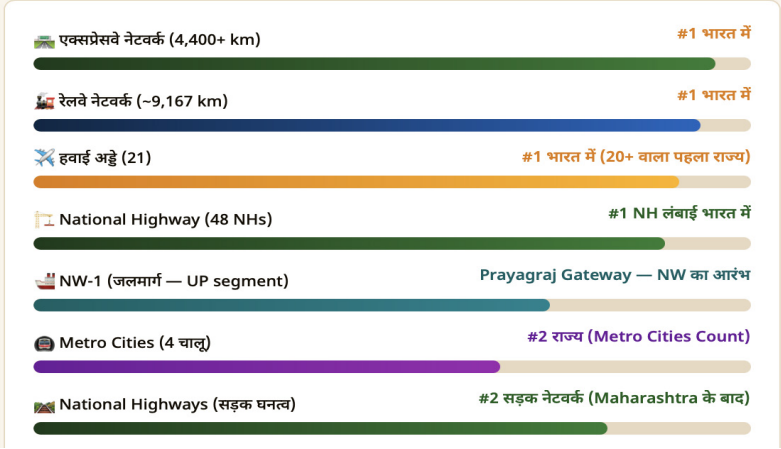

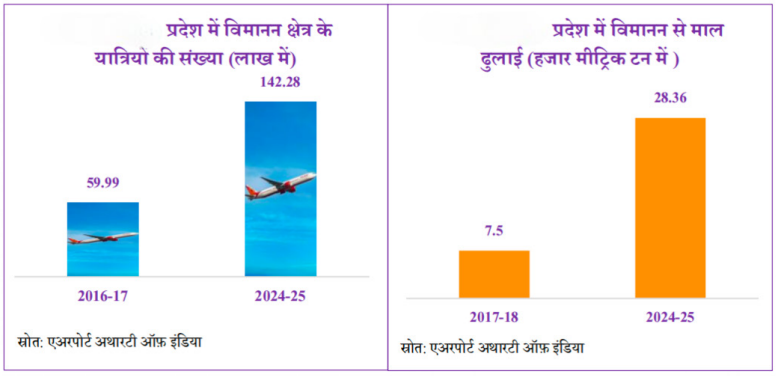

ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी जा चुकी है, यानी हवाई अड्डा सिर्फ यात्रा नहीं, उद्योग का भी प्रवेश द्वार बन रहा है।

- अयोध्या एयरपोर्ट, जो राम मंदिर उद्घाटन के साथ दिसम्बर 2023 में खुला, धार्मिक पर्यटन को एक नई उड़ान दे रहा है। अनुमान है कि राम मंदिर प्रतिवर्ष 10 करोड़ से अधिक दर्शनार्थियों को आकर्षित करेगा। कुशीनगर का एयरपोर्ट बौद्ध सर्किट को सीधे जापान, थाईलैंड और श्रीलंका से जोड़ रहा है।
- **नए हवाई अड्डे की योजना:** अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट, उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को भी एविएशन मैप पर ला रहे हैं। यूपी के 80 में से ज्यादातर जिलों को हवाई अड्डे से जोड़ने का लक्ष्य है।

जल: गंगा–व्यापार, पर्यटन और क्रांति का मार्ग

- उत्तर प्रदेश एकमात्र 'Landlocked' बड़ा राज्य है जो जलमार्ग व्यापार में भी देश में अग्रणी बन रहा है, देश के 111 जलमार्गों में से 11 उत्तर प्रदेश में हैं जो प्रदेश को नार्थ इंडिया का लॉजिस्टिक गेटवे बना रहे हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1)- भारत का सबसे लंबा जलमार्ग, 1,620 किमी लंबा, प्रयागराज से शुरू होकर हल्दिया (पश्चिम बंगाल) तक जाता है, इसका 425 किलोमीटर भाग उत्तरप्रदेश में स्थिति है।
- वाराणसी में 2018 में पीएम मोदी ने मल्टी-मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया था। 2025 में इंडिया मैरीटाइम वीक में IWAI ने NW-1 के विस्तार के लिए 6,000 करोड़ से अधिक के MoU हस्ताक्षरित किए। इनमें शामिल हैं: वाराणसी में 350 करोड़ की शिप रिपेयर फैसिलिटी, 200 करोड़ के रिवर क्रूज टर्मिनल, 800 करोड़+ प्रीमियम रिवर क्रूज टूरिज्म, 1,000 करोड़ का रेनस लॉजिस्टिक्स के साथ टग-बार्ज नेटवर्क और 200 करोड़ का रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाराणसी में।
- वाराणसी में हाइड्रोजन-ईंधन आधारित देश का पहला स्वदेशी पैसेंजर जलयान 2025 में लॉन्च हुआ, शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ। साथ ही डट गंगा विलास, विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज (3,200 किमी, 51 दिन, वाराणसी से डिब्रूगढ़), UP को global river tourism के मानचित्र पर रख चुकी है।

क्यों अहम है जलमार्ग?

- जलमार्ग से माल परिवहन की लागत सड़क से 2.5 गुना कम और रेल

से एक-तिहाई कम है। NW-1 पर कोयला, फ्लाई एश, अनाज, सीमेंट, उर्वरक और over-dimensional cargo ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर में मल्टी-मॉडल टर्मिनल से यूपी का माल सीधे कोलकाता बंदरगाह तक जाएगा।

कनेक्टिविटी से यूपी को लाभः बहुआयामी परिवर्तनः

अनुमानः आने वाले कल का यूपी

- **दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेलः** जेवर एयरपोर्ट से वाराणसी तक प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यूपी को देश की पहली हाई-स्पीड रेल गलियारा दे सकती है। यह पर्यटन और व्यापार दोनों बदल जायेंगे।
- **वाराणसी मैरीटाइम हबः** IWAI की 350 करोड़ जहाज मरम्मत सुविधा + 200 करोड़ CoE+ NW-1 कार्गो वृद्धि - वाराणसी उत्तर भारत का पहला अंतर्देशीय समुद्री सेवा केंद्र बनने की राह पर है।
- **जेवर टेक-इंडस्ट्रियल कॉरिडोरः** जेवर एयरपोर्ट +सेमीकंडक्टर यूनिट + इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर+ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे - यह पूरा क्षेत्र यूपी का 'सिलिकॉन डेल्टा' बन सकता है, जो ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाएगा।
- **डिफेंस - लॉजिस्टिक्स कॉरिडोरः** बुन्देलखण्ड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर+एक्सप्रेसवे + फ्रेट कॉरिडोर = रक्षा उत्पाद का सस्ता और तेज लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। ड्रोन, मिसाइल और विमान घटक विनिर्माण के लिए आदर्श।

औद्योगिक निवेश में बूम

बेहतर कनेक्टिविटी से UP GIS-2023 में ₹33.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। Noida-Jewar बेल्ट अब semiconductor, IT और logistics का hub बन रहा है।

किसानों को बाज़ार

Expressway और NW-1 से किसानों की उपज — गन्ना, आलू, दूध — सीधे बड़े बाज़ारों तक पहुँच रही है। Cold chain logistics सस्ती हुई है।

धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन

अयोध्या, काशी, मथुरा, कुशीनगर — सभी अब एयरपोर्ट से जुड़े। 2024 में 64.9 करोड़ पर्यटक आए। महाकुंभ 2025 ने ₹3.5 लाख करोड़ का राजस्व दिया।

रोज़गार निर्माण

एक्सप्रेसवे कॉरिडोर में हज़ारों लघु उद्योग खुले। Rozgar Melas से 13.45 लाख युवाओं को नौकरी। RRTS और मेट्रो से लाखों daily commuters की प्रोडक्टिविटी बढ़ी।

Logistics लागत में कमी

EDFC-WDFC से Dadri का माल मुंबई और कोलकाता दोनों तटों पर पहुँचता है। Jewar Airport cargo hub से UP Global Value Chain में शामिल होगा।

ग्रीन ट्रांसपोर्ट

जलमार्ग, RRTS और मेट्रो से लाखों वाहन सड़कों से हटेंगे। Hydrogen vessel Varanasi में लॉन्च। NW-1 पर Electric vessel charging infrastructure ₹100 Cr से विकसित होगा।

- **प्रयागराज मल्टीमॉडल हब:** एनडब्ल्यू-1 का आरंभ बिंदु, गंगा एक्सप्रेसवे का अंतिम छोर, रेलवे जंक्शन-प्रयागराज में एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स नोड के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- **नदी पर्यटन सर्किट:** एमवी गंगा विलास की सफलता के बाद प्रीमियम नदी पर्यटन में भारी संभावना। वाराणसी-अयोध्या-प्रयागराज क्रूज सर्किट से अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल का निर्माण किया जा सकता है।
- **हरित परिवहन क्रांति:** ईवी हाईवे कॉरिडोर, इलेक्ट्रिक वेसल चार्जिंग (100 करोड़), हाइड्रोजन वेसल्स, सौर ऊर्जा संचालित एक्सप्रेसवे – यूपी 2030 तक भारत का सस्टेनेबल मोबिलिटी लीडर बन सकता है।
- **नए शहरी गलियारे:** लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र के आसपास गंगा एक्सप्रेसवे और आरआरटीएस, 100 नए टाउनशिप – नए शहरी केंद्र, जो नोएडा-ग्रेटर नोएडा के अधिकार पर विकसित होंगे।

2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश केवल 6 हवाई अड्डे, 1 एक्सप्रेसवे और एक सोए हुए जलमार्ग के साथ जी रहा था, आज वही यूपी देश का एक्सप्रेसवे कैपिटल, पहला 20+ एयरपोर्ट राज्य और NW-1 का सबसे बड़ा मुनाफा बन चुका है। थल पर 4,400+ किमी एक्सप्रेसवे और देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, जल पर प्रयागराज से हल्दिया का 1,620 किमी जलमार्ग और 6,000 करोड़ के निवेश से बन रहा मैरीटाइम हब और नभ में 21 हवाई टर्मिनल, जेवर जैसा विश्वस्तरीय एयरपोर्ट और देश की पहली RRTS – यह तिहरी क्रांति यूपी को एक नई पहचान दे रही है।

लेखक: रवि कान्त

उड़ान भरता उत्तर प्रदेश: निवेश, उद्योग और आत्मनिर्भरता की नई इबारत

साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान थी – देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य, लेकिन आर्थिक उपलब्धियों में पिछड़ा हुआ। बिहार के बाद प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे, पलायन की त्रासदी और उद्योगों का अभाव ख़ यही न्च की छवि थी। लेकिन आज 2026 में जब हम आँकड़ों की ओर देखते हैं, तो तस्वीर बदली हुई मिलती है।

उत्तर प्रदेश का GSDP 2016–17 में रु.13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2024–25 में रु.30.25 लाख करोड़ हो गया– अर्थात करीब 10.8% की CAGRA वित्तीय वर्ष 2025–26 में यह आँकड़ा रु.36 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में UP आज महाराष्ट्र और तमिलनाडु के पीछे है, लेकिन रफ्तार उसकी सबसे तेज है।

औद्योगिक क्रांतिः निवेश का महासागर

विकास की टाइमलाइन

2017	**योगी सरकार** का आगाज़ — कानून-व्यवस्था सुधार, उद्योग-विरोधी छवि बदलने की शुरुआत
2018	**पहला GIS** — ₹4.28 लाख करोड़ के प्रस्ताव
2021	जेवर एयरपोर्ट का **भूमिपूजन**, रक्षा गलियारे की शुरुआत
2023	**GIS-2023** — 19,058 MoU, ₹33.5L Cr निवेश प्रस्ताव
2025	**महाकुंभ** — ₹3.5L Cr राजस्व, पहला आर्थिक सर्वेक्षण जारी
2026	**जेवर एयरपोर्ट** का उद्घाटन — मार्च 2026, GSDP ₹36L Cr लक्ष्य

- फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS–2023) उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक ऐतिहासिक मोड़ बन गया। इस समिट में रु.33.50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और कुल 19,058 MoU हस्ताक्षरित किए गए। अकेले IT/ITeS क्षेत्र सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा।
- IKEA ने नोएडा में रुपये 4,300 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की, UAE dh Lulu Group ने रु.2,500 करोड़ का MoU साइन किया और Adani Group ने जेवर हवाई अड्डे के नजदीक रुपये 5,500 करोड़ की वेयरहाउसिंग परियोजना की बात कही। अप्रैल 2019 से जून 2025 के बीच UP में संचयी FDI रु.17,003.75 करोड़ ($2.15 बिलियन) तक पहुँच गया।

> *"उत्तर प्रदेश अब निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। Safety, Stability और Speed — इस Triple-S Framework पर राज्य सरकार की नीतियाँ टिकी हैं।"*
>
> — UP आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25

वर्ष	GSDP (₹ लाख करोड़)	वृद्धि
2016-17	13.30	—
2020-21	18.50	+39%
2023-24	25.00+	+35%
2024-25	30.25	+21%
2025-26 (est.)	36.00	+19%

बुनियादी ढाँचा: एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक

- UP आज देश का 'एक्सप्रेसवे हब' बनता जा रहा है। 22 एक्सप्रेसवे, देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क (16,000+ किमी) और 24 हवाई अड्डों की योजना 'यह संरचना उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी है। पश्चिमी और पूर्वी Dedicated Freight Corridor (WDFC-EDFC) का संगम दादरी में होता है, जिससे UP मुंबई और कोलकाता' दोनों बंदरगाहों से जुड़ गया है।
- 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jewar Airport) का उद्घाटन किया, जो पूर्ण निर्माण के बाद विश्व के चार सबसे बड़े हवाई अड्डों में शुमार होगा। पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता है और इसे Yamuna Expressway, RRTS और Delhi-Varanasi हाई-स्पीड रेल से जोड़ा जाएगा।

सेक्टर–दर–सेक्टर: विकास की कहानी

- **रक्षा औद्योगिक गलियारा:** बुंदेलखंड और लखनऊ-अलीगढ़ रक्षा गलियारे में दर्जनों कंपनियाँ निवेश कर चुकी हैं। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कानपुर, AI हब के लिए लखनऊ और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा को क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। जेवर के पास एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी जा चुकी है।
- **डेटा सेंटर बूम:** जून 2025 तक UP में 644 MW क्षमता के डेटा सेंटर प्रस्तावित हो चुके हैं जिनमें रु.21,343 करोड़ ($2.41 बिलियन) का निवेश शामिल है। यह UP को देश के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का नया केंद्र बना रहा है।

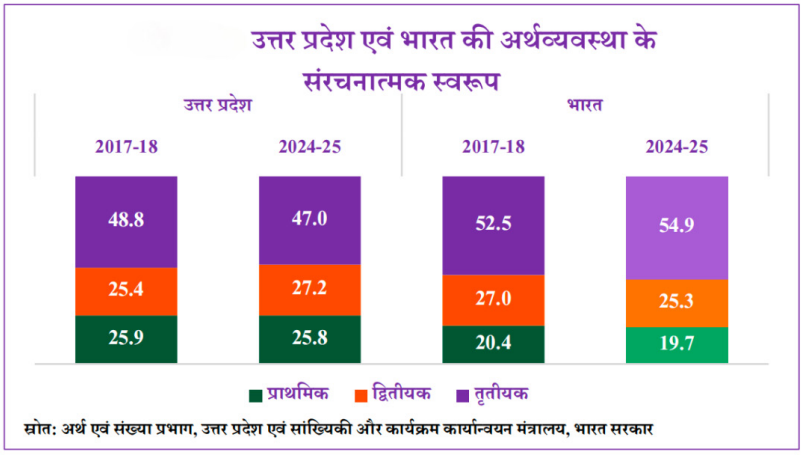

स्रोत: अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

- **कृषि और खाद्य प्रसंस्करण:** UP देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है जो भारत के कुल उत्पादन में 20.6% योगदान देता है। गन्ने और दूध उत्पादन में रु. पहले स्थान पर है-दूध उत्पादन में देश का 15.66% हिस्सा अकेले रु. का है। FY25 में GVA प्रति हेक्टेयर रु.98,000 से बढ़कर रु.1.73 लाख हो गया।
- **पर्यटन:** 2024 में UP में 64.9 करोड़ पर्यटक आए- 2023 के मुकाबले 17 करोड़ की बढ़ोतरी। 2025 के प्रयाग महाकुंभ ने 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को आकर्षित किया और अनुमानित रु. 3.50 लाख करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। राम मंदिर अयोध्या प्रतिवर्ष 10 करोड़ से अधिक दर्शनार्थियों को आकर्षित करने का अनुमान है।

चुनौतियाँ जो नजरअंदाज नहीं की जा सकतीं:

निवेश और बुनियादी ढाँचे की भव्य तस्वीर के पीछे कुछ गहरी चुनौतियाँ भी हैं जिनसे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता।

- **प्रति व्यक्ति आय का अंतर:** FY25 में UP की प्रति व्यक्ति आय रु.1,09,844 है-राष्ट्रीय औसत रु.1,97,000 से लगभग आधी। बिहार के बाद UP अभी भी देश का दूसरा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला बड़ा राज्य है।
- **असमान क्षेत्रीय विकास:** पश्चिमी UP राज्य के GDP में 71.71% योगदान देता है जबकि पिछड़ा बुंदेलखंड मात्र 5.22%। पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र निवेश की राह देख रहे हैं।
- **MoU से जमीन तक की दूरी:** GIS-2023 में हस्ताक्षरित हजारों MoU में से वास्तविक धरातल पर

लागू हुए निवेश की तस्वीर अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। MoU को वास्तविक फैक्ट्री में बदलने की प्रक्रिया धीमी है।

- **श्रम कौशल और रोजगार गुणवत्ता:** कृषि क्षेत्र में 65% आबादी लगी है जिसमें अधिकांश अर्ध-कुशल या अकुशल है। उद्योगों की माँग के अनुरूप कुशल श्रमशक्ति की भारी कमी है। नोएडा में हाल के श्रमिक आंदोलन इस असंतोष का संकेत हैं।
- **कृषि उत्पादकता की सीमाएँ:** छोटी जोतें, अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और पुरानी खेती तकनीक किसानों की आय को सीमित कर रही हैं, जबकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएँ अभी अनुपयोगी हैं।
- **लॉजिस्टिक्स लागत और इन्फ्रा गैप:** पूर्वी UP में उच्च लॉजिस्टिक्स लागत और अपर्याप्त बिजली आपूर्ति उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है। छोटे व मध्यम उद्योगों को त्मक जंचम का सामना करना पड़ता है।

समाधान: आगे की राह

चुनौतियाँ बड़ी हैं, लेकिन नीतिगत समाधान भी तैयार होते दिख रहे हैं। जरूरत है इन्हें तेजी और ईमानदारी से लागू करने की।

- **कौशल विकास का विस्तार:** रोजगार मेलों के द्वारा अब तक 13. 45 लाख युवाओं को नौकरी दिलाई गई। जापान, जर्मनी और UAE में अवसरों के लिए युवाओं को विदेशी भाषा व तकनीकी प्रशिक्षण देने की पहल जारी है।
- **निवेश मित्र - डिजिटल निकासी:** सिंगल-विंडो पोर्टल 'निवेश मित्र (Nivesh Mitra)' के जरिए निवेशकों को तेज क्लीयरेंस दी जा रही है। UP Ease of Doing Business में देशभर में दूसरे स्थान पर आ चुका है।
- **पूर्वांचल व बुंदेलखंड पर फोकस:** बुंदेलखंड रक्षा औद्योगिक कोरिडोर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिक मानचित्र पर लाने की कोशिश हो रही है। वाराणसी में IT कोरिडोर भी प्रस्तावित है।
- **ऊर्जा में आत्मनिर्भरता:** सितम्बर 2025 तक UP की कुल ऊर्जा क्षमता 35,433 MW हो गई। सौर ऊर्जा में भारी निवेश जारी है और बजट FY26 में ऊर्जा को रु.45,832 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- **क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास:** AI-Lucknow, Drone-Kanpur, IT-Noida, Textile-Varanasi, Defence-Aligarh- क्षेत्र -विशेष क्लस्टर विकास से उद्योगों को एको सिस्टम मिल रहा है और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो रही है।
- **कृषि आधुनिकीकरण:** बीज पार्क, दलहन मिशन और तिलहन विविधी करण के लिए कृषि मशीनरी शेयरिंग जारी है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से किसानों की आय वृद्धि का लक्ष्य है।

निष्कर्ष: अधूरी है, पर सही है यह यात्रा

उत्तर प्रदेश की आर्थिक यात्रा न तो सरल है, न पूर्ण। रु.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 30,000 से ज्यादा फैक्ट्रियाँ, जेवर एयरपोर्ट और 22 एक्सप्रेसवे - ये उपलब्धियाँ वास्तविक हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय की खाई, क्षेत्रीय असमानता और MoU से जमीनी निवेश के बीच की दूरी- ये चुनौतियाँ भी उतनी ही वास्तविक हैं। 2027 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना महत्वाकांक्षी है, लेकिन अगर नीतियाँ जमीन तक पहुँचती रहीं और असमानता कम होती रही, तो UP की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। यह राज्य अब सिर्फ संख्या का प्रदेश नहीं - संभावना का प्रदेश है।

लेखक: गौतम शुक्ला

NEWS DRIFT

तथ्य • निष्पक्षता • प्रभाव

मई 2026 के अगले अंक में पढ़ें :

उत्तर प्रदेश में 9 वर्षों का स्वास्थ्य सफर:

बदला कितना, बाकी कितना?

- अस्पतालों की संख्या में वृद्धि
- डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता
- स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता
- जनता की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार?

खास रिपोर्ट्स:

- स्वास्थ्य ढांचे में कितना विस्तार हुआ?
- सरकारी योजनाओं का जमीनी असर
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में क्या सुधार?
- डिजिटल हेल्थ और टेलमेलोंजी की भूमिका
- चुनौतियों अभी भी कितनी बाकी?

एक विस्तृत विश्लेषण
तथ्यों और जमीनी हकीकत के साथ

तैयार रहिए, एक ज़रूरी और असरदार रिपोर्ट के लिए!

Follow us: | www.newsdrift.in | संपर्क करें: newsdrift19@gmail.com

News Drift

Changing News Trend

Online

News Portal

Stay

UPTO DATE

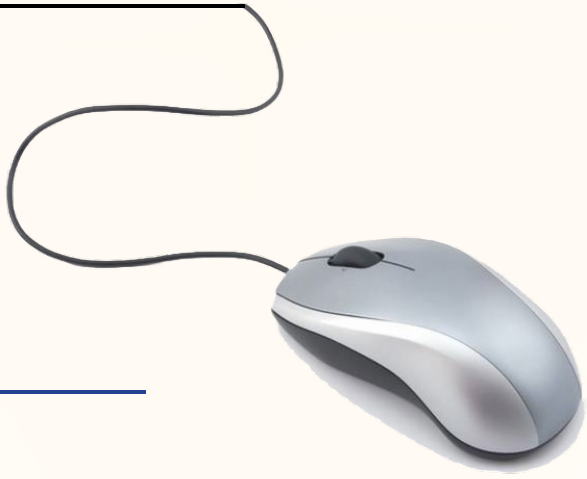

www.newsdrift.in

Email- newsdrift19@gmail.com

Instagram- newsdrift.official